सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
YouTube

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

परिवहन विशेष

www.newsparivahan.com
वर्ष 02, अंक 38, नई दिल्ली । शनिवार, 20 अप्रैल 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8
देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

सफल बनने के लिए सबसे पहले असफलता का डर मन में से निकालना चाहिए।

03 डीयू में 25 अप्रैल से शुरू होगी PG के लिए दाखिले की दौड़....
06 कांग्रेस का सिमटता प्रभाव और खतरनाक सोच
08 21 राज्यों की 102 सीटों पर पहला फेज संपन्न

दिल्ली परिवहन विभाग सार्वजनिक सेवा वाहनों में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कितना जागरूक, जाने

संजय बाटला

दिल्ली भारत देश की राजधानी किसी देश की राजधानी में अगर

1. सार्वजनिक सवारी वाहनों में महिला बेखौफ (दिन हो या रात) सुरक्षित सफर ना कर सके तो आप क्या कहेंगे ?

2. अगर महिला सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार राजधानी का परिवहन विभाग हो तो आप क्या कहेंगे ?

3. महिला सुरक्षा के प्रति अगर गृह मंत्रालय सचिव कमेटी एवम् माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को सुरक्षा मुहैया कराने की जगह राजस्व में इज़ाफा करवाने में परिवहन विभाग सम्मिलित हो तो आप क्या कहेंगे ?

4. महिलाओं की सुरक्षा के प्रति गृह मंत्रालय सचिव कमेटी एवम् माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को पूरा करने के लिए परिवहन विभाग को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पैसा मिला हो और फिर भी परिवहन विभाग महिलाओं की सुरक्षा की जगह राजस्व में इज़ाफा करवाने में लगा हुआ हो तो आप क्या कहेंगे ?

जी हां, भारत देश की राजधानी दिल्ली के परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए आए आदेशों का पालन महिलाओं को सुरक्षा मुहैया करने की जगह राजस्व में इज़ाफा करने के लिए किया। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से महिलाओं की सुरक्षा के प्रति **"निर्भया फ्रेमवर्क के तहत एआईएस -140 मानक के अनुसार सार्वजनिक सेवा वाहनों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए निगरानी केन्द्र के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त 80% पैसों के बाद भी निगरानी केन्द्र बनवाए बिना बकाया 20% को प्राप्त करने की कोशिश शुरु है।** जिस सरकारी विभाग को सुरक्षा मुहैया करवाने का जिम्मा सौंपा गया हो अगर वह ही सुरक्षा मुहैया कराने की जगह राजस्व में इज़ाफा करवाने में लगा हो तो आप क्या कहेंगे ? अब हम आपकों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा ट्रैकिंग और निगरानी केन्द्र के कार्यान्वयन के लिए हुए समझोता ज्ञापन (एमओयू) की कुछ जरूरी बाते बता रहा हूं, इन्हे पढ़ने के बाद अपनी राय/प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करना की **जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसका क्या करना चाहिए**

नोटः- **वीएलटीडी/ पैनिक बटन/ सीसीटीवी कैमरे की ट्रैकिंग और निगरानी के नाम पर अरबों रुपए वाहन मालिकों से परिवहन विभाग ले चुका है और अभी भी लेना चालू है वह भी निगरानी केन्द्र बनवाए बिना**

"एमओयू का पृष्ठ 4 और 5 आपकी जानकारी हेतु"

इस एमओयू की शर्तों के अनुसार, उपरोक्त दायरे की लागत को योजना के तहत वित्त पोषण के उद्देश्य से केवल परियोजना लागत के रूप में माना जाएगा।

5. MORTH की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

MoRTH की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ इस प्रकार होंगीः

निगरानी केंद्र की स्थापना के लिए मानक दिशानिर्देश और निर्देश प्रदान करके (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश) को समर्थन देना

निर्भया फ्रेमवर्क के अनुसार [राज्य/केंद्र शासित प्रदेश) में निगरानी केंद्र की स्थापना के लिए धन सहायता प्रदान करना

हितधारकों के बीच समन्वय करने, परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने, डिलिवरेबल्स और कार्यान्वयन/संचालन रिपोर्ट की समीक्षा करने, भुगतान जारी करने की सिफारिश करने और उपयोग प्रमाणपत्रों के विरुद्ध भुगतान का समाधान करने के लिए

DIMTS लिमिटेड के माध्यम से MoRTH में एक राष्ट्रीय पीएमयू स्थापित करें।

VAHAN के साथ एकीकरण के लिए सहायता प्रदान करना

आवश्यकताओं के अनुसार गृह मंत्रालय और अन्य विभागों के साथ समन्वय

6. (राज्य/केंद्रशासित प्रदेश) की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

{राज्य/केंद्र शासित प्रदेश] की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां इस प्रकार होंगीः

योजना दिशानिर्देशों के अनुसार निगरानी केंद्र की स्थापना।

निगरानी केंद्र की स्थापना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी की नियुक्ति।

अपने अंशदान का समय पर भुगतान सुनिश्चित करके परियोजना का समर्थन करें।

परियोजना कार्यान्वयन के लिए एक नोडल अधिकारी और एक पीआईयू नियुक्त करें। [राज्य/केंद्र शासित प्रदेश] परियोजना के कार्यान्वयन में सहायता के लिए एक पीएमसी भी नियुक्त कर सकता है। परियोजना कार्यान्वयन के संबंध में सभी पत्राचार और समन्वय के लिए नोडल अधिकारी संपर्क का एकमात्र बिंदु होगा।

सुनिश्चित करें कि निगरानी केंद्र राज्य ईआरएसएस/अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली से जुड़ा हुआ है।

सुनिश्चित करें कि निगरानी केंद्र योजना दिशानिर्देशों में MoRTH द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाओं का अनिवार्य रूप से अनुपालन करता है।

सीएमवीआर और एमओआरटीएच अधिसूचनाओं/दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार विभिन्न गतिविधियाँ करना जैसे परमिट धारकों/वीएलटी निर्माताओं/आरटीओ अधिकारियों आदि को आवश्यक आदेश/दिशा-निर्देश जारी करना।

सुनिश्चित करें कि निर्दिष्ट सार्वजनिक सेवा वाहनों का पंजीकरण/फिटनेस आरटीओ स्तर पर वाहन/[राज्य/केंद्रशासित प्रदेश] द्वारा उपयोग किए जा रहे किसी भी अन्य वाहन पंजीकरण प्रणाली में वीएलटी डिवाइस की फिटमेंट और कार्यात्मक स्थिति की जांच के बाद ही किया जाता है।

निगरानी केंद्र को वाहन/उपयोग में आने वाले किसी अन्य वाहन पंजीकरण प्रणाली के साथ एकीकृत करें।

प्रस्तावित प्रणाली का उपयोग करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में डेस्कटॉप और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करें।

निगरानी केंद्र का ओ एंड एम

जब तक राज्य इस योजना के तहत निगरानी केंद्र स्थापित नहीं करता, तब तक वह MORTH दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भी बैकएंड सिस्टम का उपयोग करके VAHAN/राज्य वाहन पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से 1 जनवरी 2019 के बाद पंजीकृत वाहनों के लिए CMVR 125H का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

7. परियोजना लागत और भुगतान शर्तें

MORTH वास्तविक परियोजना लागत का (योजना के अनुसार प्रतिशत) अधिकतम रु. का भुगतान करेगा। (योजना के अनुसार राशि), रुपये की कटौती के बाद. [योजना के अनुसार राशि) आनुपातिक आधार पर एनआईसी क्लाउड, राष्ट्रीय पीएमयू और एमओआरटीएच डैशबोर्ड के लिए।

उपरोक्त कटौती के बाद MORTH शेयर का भुगतान नीचे दिए गए लक्ष्यों के अनुसार होगाः

1. मील का पत्थर भुगतान 80%
2. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निगरानी केंद्र की स्थापना
3. कमीशनिंग के बाद मॉनिटरिंग सेंटर का तीन महीने तक सफल संचालन 20%

नोटः टी योजना के तहत वित्त पोषण के लिए MoRTH द्वारा जारी किए गए मंजूरी पत्र की तारीख होगी।

प्रारंभिक भुगतान MORTH द्वारा अग्रिम के रूप में जारी किया जाएगा। बाद में भुगतान एमओआरटीएच पीएमयू द्वारा जांच के बाद प्राप्त मील के पत्थर के विरुद्ध जारी किए जाएंगे।

[राज्य/केंद्र शासित प्रदेश] एक मील का पत्थर हासिल करने पर MoRTH को कार्यान्वयन/संचालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। MoRTH (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश) से अपेक्षित कार्यान्वयन/संचालन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद भुगतान का अपना हिस्सा जारी करेगा।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 31 दिसंबर 2020 तक निगरानी केंद्र की शुरूआत सुनिश्चित करेंगे।

(राज्य/केंद्र शासित प्रदेश) से कार्यान्वयन/संचालन रिपोर्ट की जांच और समीक्षा एमओआरटीएच पीएमयू द्वारा दूसरे भुगतान जारी करने से पहले की जाएगी, जो कि निगरानी केंद्र के सफल संचालन के तीन महीने बाद उसके चालू होने के बाद जारी की जाएगी।

एमओआरटीएच में एनआईसी क्लाउड, राष्ट्रीय पीएमयू और डैशबोर्ड की लागत एमओआरटीएच द्वारा रखी जाएगी और आनुपातिक राशि को समायोजित करने के बाद (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश) को धनराशि जारी की जाएगी।

"आपके विचार और जवाब का इन्तजार"

इस समय पूरे देश की यह राष्ट्रीय समस्या है यह कोई निजी समस्या नहीं है गंभीर समस्या पूरे देश में यह राष्ट्रीय समस्या दिन प्रतिदिन बनती जा रही है देवेंद्र सिंह

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। इलीगल स्कूल कॉलेज वैन पूरे देश में चलती हुई सीसीटीवी की निगरानी में

इलीगल Van पूरे देश में चलती हुई सीसीटीवी की निगरानी में सड़कों पर एवं अन्य कमर्शियल कार्यों के लिए

इलीगल बस पूरे देश में चलती हुई सीसीटीवी की निगरानी में सड़कों पर एवं अन्य जगह

पूरे देश के अंदर जुगाड़ चलते हुए सीसीटीवी की निगरानी में सड़कों पर एवं अन्य जगह

पूरे देश के अंदर गाय भैंस सांड बकरी एवं अन्य जानवर सड़कों पर चलते हुए सीसीटीवी की निगरानी में एवं अन्य जगह

पूरे देश के अंदर पुलिस थानों में एवं आरटीए के ऑफिस में खड़े हुए Vahan

समस्या का समाधान मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत सबसे सख्त कार्रवाई एवं समस्या को जड़ से खत्म करना चाहिए

पूरे देश का राजस्व ट्रांसपोर्ट का चोरी करते हुए अब इसके लिए जिम्मेदार कौन यह एक राष्ट्रीय समस्या है जबकि भारत सरकार के द्वारा एवं अन्य सरकारों के द्वारा सब की जिम्मेदारी फिक्स की हुई है

इसके लिए हम सभी को जागना होगा और जागना होगा और राष्ट्रीय समस्या का समाधान करना होगा

सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा

स्पेशल नोट सबसे पहले राष्ट्रीय समस्या को जो भी इसके स्टेक होल्डर हैं उनके साथ संवाद करना होगा उनकी समस्या समझ नहीं होगी और फिर इसका समाधान एवं ग्राउंड लेवल पर तुरंत एक्शन करना होगा।

परिवहन आयुक्त उत्तराखंड, देहरादून द्वारा देश के पर्वतीय मार्गो पर वाहनों के व्हील बेस के पुन निर्धारण के सम्बंध में जारी किया आदेश जाने

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

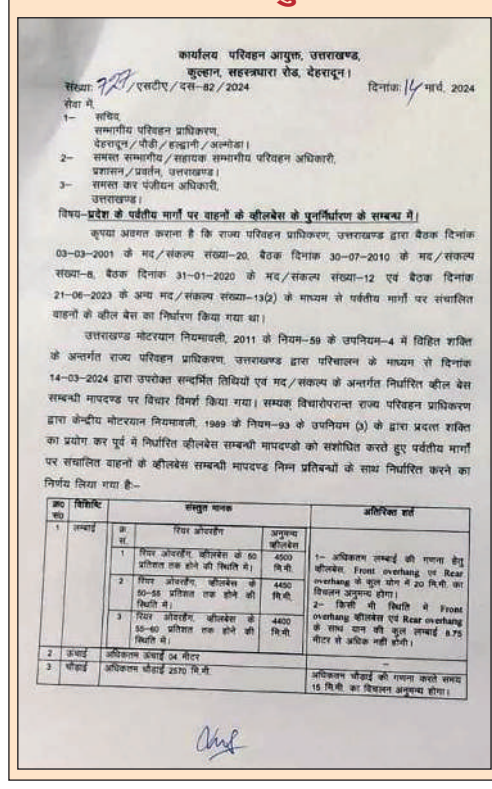

संख्याः 727/एसटीए/दस-82/2024 दिनांकः 14 मार्च, 2024

सेवा में,
1- सचिव,
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण,
देहरादून/पौड़ी/हल्द्वानी/अल्मोड़ा।
2- समस्त सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
प्रशासन/प्रवर्तन, उत्तराखण्ड।
3- समस्त कर पंजीयन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय-प्रदेश के पर्वतीय मार्गों पर वाहनों के व्हीलबेस के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा बैठक दिनांक 03-03-2001 के मद/संकल्प संख्या-20, बैठक दिनांक 30-07-2010 के मद/संकल्प संख्या-8, बैठक दिनांक 31-01-2020 के मद/संकल्प संख्या-12 एवं बैठक दिनांक 21-06-2023 के अन्य मद/संकल्प संख्या-13(2) के माध्यम से पर्वतीय मार्गों पर संचालित वाहनों के व्हील बेस का निर्धारण किया गया था।

उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम-59 के उपनियम-4 में विहित शक्ति के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा परिचालन के माध्यम से दिनांक 14-03-2024 द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित तिथियों एवं मद/संकल्प के अन्तर्गत निर्धारित व्हील बेस सम्बन्धी मापदण्ड पर विचार विमर्श किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-93 के उपनियम (3) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर पूर्व में निर्धारित व्हीलबेस सम्बन्धी मापदण्डो को संशोधित करते हुए पर्वतीय मार्गों पर संचालित वाहनों के व्हीलबेस सम्बन्धी मापदण्ड निम्न प्रतिबन्धों के साथ निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है:-

क्र0 सं0	विशिष्टि	संस्तुत मानक			अतिरिक्त शर्त
		क्र. सं.	रियर ओवरहैंग	अनुमन्य व्हीलबेस	
1	लम्बाई	1	रियर ओवरहैंग, व्हीलबेस के 50 प्रतिशत तक होने की स्थिति में।	4500 मि.मी.	1- अधिकतम लम्बाई की गणना हेतु व्हीलबेस, Front overhang एवं Rear overhang के कुल योग में 20 मि.मी. का विचलन अनुमन्य होगा। 2- किसी भी स्थिति में Front overhang व्हीलबेस एवं Rear overhang के साथ यान की कुल लम्बाई 8.75 मीटर से अधिक नहीं होगी।
		2	रियर ओवरहैंग, व्हीलबेस के 50-55 प्रतिशत तक होने की स्थिति में।	4450 मि.मी.	
		3	रियर ओवरहैंग, व्हीलबेस के 55-60 प्रतिशत तक होने की स्थिति में।	4400 मि.मी.	
2	ऊंचाई	अधिकतम ऊंचाई 04 मीटर			-
3	चौड़ाई	अधिकतम चौड़ाई 2570 मि.मी.			अधिकतम चौड़ाई की गणना करते समय 15 मि.मी. का विचलन अनुमन्य होगा।

2- राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 31.01.2020 के संकल्प संख्या-12 के अन्तर्गत देहरादून-मसूरी, टनकपुर-पिथौरागढ़-धारचूला, ज्योतिकोट-भवाली-खैरना-क्वारब-अल्मोड़ा एवं हल्द्वानी-नैनीताल तथा बल्दियाखान मार्गों पर व्हीलबेस के सम्बन्ध में निर्धारित मापदण्ड पूर्ववत रहेंगे।

3- उक्त मापदण्डों की प्रभावशीलता तथा व्यापकता मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या-31/2012 प्रो0 अजय रावत बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेशों के अधीन होगी।

(सनत कुमार सिंह)
सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि:- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सनत कुमार सिंह)
सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

दोष देना बंद करें, कार्रवाई शुरू करें: सड़क सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी का आह्वान

आज के समाज में, समस्याएँ आने पर उँगलियाँ उठाना और दोष मढ़ना बहुत आसान है। चाहे वह सड़क सुरक्षा से संबंधित हो या व्यापक सामाजिक मुद्दे, जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की प्रवृत्ति प्रचलित है। हालाँकि, सक्रिय रूप से समाधान खोजे बिना केवल समस्याओं की पहचान करना उन मुद्दों को कायम रखता है जिनका हम समाधान करना चाहते हैं।

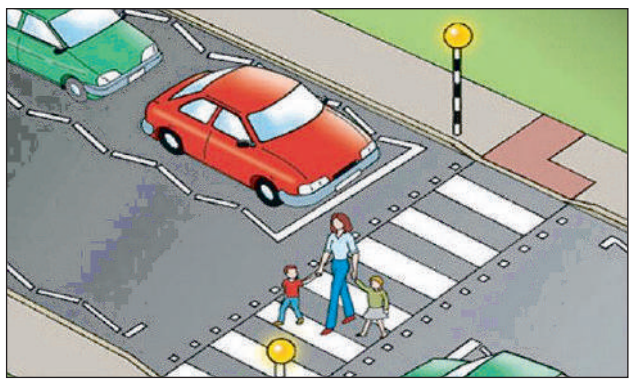

मामले की जड़ स्वामित्व लेने और परिवर्तन शुरू करने के प्रति हमारी सामूहिक अनिच्छा में निहित है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि स्थिति को सुधारने के लिए कोई और कदम उठाएगा, जिससे निष्क्रियता और हताशा का चक्र शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम वास्तव में प्रगति और सुधार चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि हम एक सक्रिय मानसिकता अपनाएं।

सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर विचार करें, एक ऐसी चिंता जो उम्र, लिंग या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी को प्रभावित करती है। ख़राब स्ट्रीटलाइट्स से लेकर उपेक्षित गड्ढों तक, अगर ध्यान न दिया जाए तो छोटी-मोटी रुकावटें बड़े खतरों में तब्दील हो सकती हैं। अधिकारियों या बुनियादी ढांचे पर दोष मढ़ने के बजाय, हमें अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने में हितधारकों के रूप में अपनी भूमिका को पहचानना चाहिए।

उदाहरण के लिए, टूटी हुई स्ट्रीटलाइट की मरम्मत के लिए किसी सरकारी एजेंसी की प्रतीक्षा करने के बजाय, व्यक्ति समस्या की रिपोर्ट करने की पहल कर सकते हैं और इसे हल करने में सहायता भी दे सकते हैं। स्विच फ़्लिप करने या उपयुक्त अधिकारियों को सचेत करने जैसी सरल कार्रवाइयां दुर्घटनाओं को रोक सकती हैं और समग्र सड़क सुरक्षा में सुधार कर सकती हैं।

इसी तरह, गड्ढों के बढ़ने से मोटर चालकों और पैदल चलने वालों दोनों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हालाँकि फुटपाथ में एक छोटी सी दरार को नज़रअंदाज करना आसान है, लेकिन समस्या का समाधान करने की उपेक्षा करने से स्थिति और बिगड़ जाती है। गड्ढों की रिपोर्ट करने और समय पर मरम्मत की वकालत करने के लिए समय निकालकर, हम दुर्घटनाओं के जोखिम को कम कर सकते हैं और अपने सड़क मार्गों की अखंडता को बनाए रख सकते हैं।

इसके अलावा, व्यापक सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए जवाबदेही और सामाजिक जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देना आवश्यक है। चाहे वह पर्यावरण संरक्षण की वकालत हो या समावेशिता और विविधता को बढ़ावा देना, सकारात्मक परिवर्तन लाने में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका होती है।

अपने दृष्टिकोण को एक दोष से एक कार्य तक पुनः परिवर्तित करके, हम स्वयं को प्रगति के लिए उत्प्रेरक बनने के लिए सशक्त बनाते हैं। हम सभी को प्रभावित करने वाली समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों की प्रतीक्षा करने के बजाय, आइए हम अपनी सामूहिक भलाई का स्वामित्व लें और ठोस समाधान की दिशा में काम करें।

उंगली उठाने और निष्क्रियता का समय ख़त्म हो गया है. अब दोषारोपण बंद करने और कार्रवाई शुरू करने का समय आ गया है। चाहे वह सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना हो या व्यापक सामाजिक मुद्दों का समाधान करना हो, हममें से प्रत्येक के पास बदलाव लाने की शक्ति है। आइए अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, अधिक न्यायसंगत दुनिया बनाने के अवसर का लाभ उठाएं।

डॉ अंकुर शरण (राष्ट्रीय मुख्य यातायात एवं योजना अधिकारी, सड़क सुरक्षा ओमनी फाउंडेशन)

"सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना: सुरक्षित भारत के लिए एक सामूहिक जिम्मेदारी" #AccidentFreeBharat : डॉ अंकुर शरण

एक सुरक्षित भारत की खोज में, सड़क सुरक्षा को महज जागरूकता से आगे बढ़कर एक ऐसी आदत बनना चाहिए, जो हमारे समाज के ढांचे में गहराई से निहित हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक सड़क सुरक्षा मैनुअल के पन्नों में निहित है, एक ऐसा दस्तावेज़ जिसे न केवल शैक्षणिक संस्थानों में अपना स्थान मिलना चाहिए बल्कि इसे हमारे दैनिक जीवन के मूलभूत घटक के रूप में भी अपनाया जाना चाहिए।

सड़क सुरक्षा शिक्षा का सार न केवल ज्ञान प्राप्त करने में बल्कि इसके दृढ़ कार्यान्वयन में भी निहित है। सुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों को समझना केवल पहला कदम है। सच्ची जागरूकता इस ज्ञान को सड़कों पर लगातार लागू करने से आती है, चाहे कोई गाड़ी चला रहा हो या यात्री।

अफसोस की बात है कि वास्तविकता अक्सर इस आदर्श से कम होती है। सड़क सुरक्षा के महत्व से अवगत होने के बावजूद, कई व्यक्ति जब अपनी दैनिक दिनचर्या में इसके कार्यान्वयन की बात करते हैं तो लड़खड़ा जाते हैं। चाहे वह गाड़ी चलाते समय किसी टेक्स्ट संदेश पर नज़र डालने का प्रलोभन हो या छोटी यात्रा के दौरान सीट बेल्ट पहनने की उपेक्षा हो, इन प्रतीत होने वाली हानिरहित क्रियाओं के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।

यदि संगीत को सार्वभौमिक भाषा माना जाता है, तो सड़क सुरक्षा को एक ऐसी आदत के रूप में माना जाना चाहिए जो समय या स्थान की कोई सीमा नहीं जानती। इसे हमारी प्राथमिकताओं में पीछे नहीं रखा जाना चाहिए, केवल संकट के क्षणों में ही इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके बजाय, इसे हमारे जीवन के हर पहलू में शामिल होना चाहिए, सड़क पर हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए और जिम्मेदारी और सतर्कता की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए।

वास्तव में दुर्घटना-मुक्त भारत #AccidentFreeBharat का लक्ष्य हासिल करने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी और दूसरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। सड़क सुरक्षा मैनुअल की शिक्षाओं को अपनाना केवल एक दायित्व नहीं है बल्कि हमारे समुदायों की भलाई के लिए एक प्रतिबद्धता है। आइए हम सड़क सुरक्षा को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने का संकल्प लें, यह सुनिश्चित करें कि हर यात्रा एक सुरक्षित, दुर्घटना मुक्त भारत की दिशा में एक कदम हो।

मां बनने की राह में रोड़ा बनती है यह बीमारी, गर्भाशय में दीमक की तरह करती है काम, डॉक्टर से जानें कारण और बचाव

मां बनना हर महिला के लिए एक सुखद अहसास है. लेकिन, तमाम ऐसी बीमारी हैं जो मां बनने की राह में रोड़ा बनने का काम करती हैं. एंडोमेट्रिओसिस (endometriosis) बीमारी इनमें से एक है. यह महिलाओं के गर्भाशय में होती है, जिसमें गर्भाशय के अंदर एंडोमेट्रियम टिश्यू बनता है. एंडोमेट्रियम परत बढ़ने पर गर्भाशय के बाहर की ओर फैलने लगती है. फिर ये धीरे-धीरे अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब या अन्य प्रजनन अंगों तक फैलती है।t

एंडोमेट्रियम परत के बढ़ने से वजाइना के मुख पर अतिरिक्त कोशिकाओं का विकास भी हो जाता है. जब यह परत फेलोपियन ट्यूब तक फैलती है तो इससे अंडाशय की क्षमता पर असर पड़ता है. जोकि इंफर्टिलिटी का कारण बनता है. क्योंकि स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाता. जब एंडोमीट्रीओसिस शरीर के अंदर के ऑर्गन्स आंतों, किडनी वगैरह को प्रभावित करता है तो उस स्थिति को 'फ्रोजेन पेल्विस' कहा जाता है. अब सवाल है कि यह बीमारी गर्भाशय को कैसे नुकसान पहुचाती है? मां बनने में कैसे बनती है बाधा? इन सवालों के बारे में राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज की गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. अमृता साहा ने News18 को विस्तार से बताया है।

क्या होता है फेलोपियन ट्यूब?

डॉ. अमृता साहा के मुताबिक, गर्भाशय के दोनों तरफ ओवरी होती है, और ओवरी गर्भाशय से फैलोपियन ट्यूब द्वारा जुड़ी होती है. एंडोमेट्रिओसिस को लोग पीरियड्स दर्द या गर्भाशय-गांठ कह देते हैं. दुनिया भर में इस बीमारी के ट्रीटमेंट से लेकर लक्षणों की जानकारी की कमी है. यह रोग गर्भाशय में दीमक की तरह है।

एंडोमेट्रिओसिस क्यों होता है?

यह बीमारी बाहरी संक्रमण की वजह से नहीं, बल्कि शरीर की आंतरिक प्रणाली में कमी के कारण होती है. इन वजहों में से एक महिलाओं की खराब जीवनशैली से तनाव में रहना भी एक है. इसके साथ ही एन्डोमीट्रीओसिस की वजह इम्युनिटी खराब रहना, गर्भाशय में अतिरिक्त कोशिकाओं का निर्माण होना या फिर किसी प्रकार के घाव या सर्जरी से भी इसकी वजह हो सकती है।

एंडोमेट्रिओसिस के लक्षण क्या हैं?

मासिक धर्म के दौरान असाहनीय दर्द एंडोमेट्रिओसिस के प्रमुख लक्षणों में से एक है. कई बार यह दर्द पूरे महीने तक रहता है. इसके अलावा, पीठ में दर्द रहना, कंधों में दर्द रहना, जांघों में तेज दर्द होना, डायरिया, कब्ज, यूरिन में खून आना, शरीर के निचले हिस्से में जकड़न, पीरियड्स से पहले मांसपेशियों में खिंचाव या फिर पीरियड्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना भी शामिल हैं।

इस बीमारी से होने वाली परेशानियां

एंडोमेट्रिओसिस बीमारी से पीड़ित महिलाओं को पेट दर्द रहना सबसे बड़ी परेशानी है. इसके अलावा, हड्डियों में दर्द रहना, चेहरे पर झाइयां, बाल झड़ना या सफ़ेद होना, भूलने लगना, इरिटेट होना, हाई बीपी, किडनी का कमज़ोर होते जाना, आंखों की रोशनी कम होने की परेशानियां होती हैं. वहीं, इस बीमारी से ग्रस्त महिला कंसीव नहीं कर पाती, क्योंकि स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाता है।

एंडोमेट्रिओसिस से ऐसे करें बचाव

डॉ. साहा के अनुसार, शरीर में एंडोमेट्रियोसिस होने की संभावना एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर के बढ़ने के कारण होती है. यदि एंडोमेट्रियल की समस्या हो रही है तो इसे रोक पाना मुश्किल है, इसलिए शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन को कम करके एंडोमेट्रियोसिस होने की संभावना से बचाव किया जा सकता है. दरअसल, एस्ट्रोजन मासिक धर्म चक्र के समय गर्भाशय की लाइनिंग मोटी हो जाती है. इसके लिए हार्मोनल गर्भनिरोधक दवाओं या गर्भनिरोधक उपचारों के माध्यम से एस्ट्रोजन का लेवल कम किया जा सकता है, लेकिन बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के यह दवाएं नहीं लेनी चाहिए. इसके अलावा, नियमित व्यायाम और कम कैफीन युक्त पदार्थों के सेवन से भी एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम किया जा सकता है. वहीं, इसके इलाज के तौर पर हिस्टेरेक्टॉमी नाम की सर्जरी भी की जाती है. जिसमें गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा को हटाने के साथ-साथ दोनों अंडाशय भी निकाले जाते हैं।

स्नैक्स में बनाएं सफेद काबुली चने का फलाफल, खाने का स्वाद हो जाएगा दोगुना

फलाफल बनाने के लिए सफेद काबुली चने को एक रात पहले भिगोकर रख दें। क्योंकि फलाफल बनाने के लिए सफेद काबुली चनों को 5-7 घंटे के लिए भिगोना जरूरी होता है। स्वादिष्ट फलाफल बनाकर आप चाय के साथ खा सकते हैं।

कई लोगों को फलाफल काफी पसंद है। ऐसे में अगर आपको क्रिस्पी और कुरकुरे स्नैक्स खाना पसंद है, तो आपको फलाफल का स्वाद जरूर अच्छा लगेगा। बता दें कि फलाफल को सफेद काबुली चने से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सफेद काबुली चने को एक रात पहले भिगोकर रख दें।

क्योंकि फलाफल बनाने के लिए सफेद काबुली चनों को 5-7 घंटे के लिए भिगोना जरूरी होता है। स्वादिष्ट फलाफल बनाकर आप चाय के साथ खा सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी फलाफल बनाना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको फलाफल बनाने की रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं।

सामग्री: सबूत धनिया- 1 बड़ा चम्मच, लाल शिमला मिर्च, जीरा- 1 चम्मच, छोले- 2 कप (भीगे हुए), लहसुन- 5-6, लाल सूखी मिर्च- 4, सफेद सिरका- 1 बड़े चम्मच, अजमोद के पत्ते- 8-10, नमक- स्वादानुसार, तेल- तलने के लिए

ऐसे बनाएं

ऊपर बताई गई सामग्रियों को एकत्र कर लें, फिर एक पैन को गर्म करने के लिए गैस पर रख दें। पैन के गर्म होने के बाद सूखा धनिया और जीरा डालकर भूनें। जब यह भुन जाएं, तो इसको थोड़ा ठंडा होने दें।

इसके बाद शिमला मिर्च को छीलें और बीच से आधे हिस्से में काट दें। शिमला मिर्च के बीजों को निकालकर कैप्सिकम के मोटे पीस काट लें।

अब एक भिगोए हुए छोले को फूड प्रोसेसर में डालकर उसमें भुना हुआ जीरा और धनिया डालें। इसके बाद इसमें लहसुन, लौंग, कटा हुआ शिमला मिर्च, नमक, भिगोए हुए लाल मिर्च, अजमोद के पत्तों और सिरका डालकर पीस लें।

फिर एक कड़ाही में तेल गर्म कर मिश्रण के छोटे-छोटे हिस्से लें। इसको एक शेप दें और गर्म तेल में डालकर दोनों तरफ से सुनहरा-भूरा व कुरकुरा होने तक भूनें।

इस तरह से स्वादिष्ट और कुरकुरे फलाफल बनकर तैयार हो जाएंगे। इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल कर लाल मिर्च पाउडर और जैतून के तेल के साथ गॉर्निश कर सर्व करें।

नवजात बच्चे को 6 माह से पहले नहीं देना चाहिए ठोस आहार

ऐसे में पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चों को किस उम्र से ठोस आहार देना शुरू करना चाहिए। ऐसे में बतौर पेरेंट्स आपके मन भी यह सवाल है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि 6 माह की उम्र से पहले बच्चे को ठोस आहार देने से क्या होता है।

नवजात बच्चों को अक्सर 6 महीने बाद ठोस आहार खिलाए जाने की सलाह दी जाती है। लेकिन कई बार दादी-नानी बच्चों को महज 4 महीने की उम्र से चावल को मसलकर या दाल का पानी और फल आदि खिलाना शुरूकर देते हैं। डॉक्टर के अनुसार, बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए उन्हें कम उम्र से ठोस पदार्थ खिलाना शुरूकर देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर कम से कम 6 माह तक बच्चे को सिर्फ मां का दूध पिलाने की सलाह देते हैं।

ऐसे में पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चों को किस उम्र से ठोस आहार देना शुरू करना चाहिए। ऐसे में बतौर पेरेंट्स आपके मन भी यह सवाल है, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि 6 माह की उम्र से पहले बच्चे को ठोस आहार देने से क्या होता है।

6 महीने से पहले क्यों न खिलाएं ठोस आहार

बता दें कि डॉक्टर 6 माह से कम उम्र वाले बच्चों को ठोस आहार खिलाने से बचने की सलाह देते हैं। क्योंकि 6 माह से कम उम्र के बच्चों को ठोस आहार खिलाने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। क्योंकि इस उम्र के बच्चों का पाचन तंत्र पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है। जिस कारण उन्हें ठोस आहार पचाने में समस्या होती है। इसलिए उन्हें कब्ज, दस्त या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। वहीं 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को ठोस आहार देने से उनमें एलर्जी का खतरा भी बढ़ जाता है। क्योंकि इस दौरान उनकी इम्यूनिटी विकसित हो रही होती है।

कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं, जो बच्चों की इम्यूनिटी पर बुरा असर डाल सकते हैं। साथ ही ठोस आहार खिलाने से फॉर्मूला फीडिंग या स्तनपान करने में समस्या आ सकती है। क्योंकि स्तनपान से बच्चों में पोषक तत्वों की कमी पूरी होती है। इसलिए 6 माह तक बच्चे को सिर्फ मां का दूध पिलाए जाने की सलाह दी जाती है। इससे बच्चे की इम्यूनिटी मजबूत होती है और वह स्वस्थ रहते हैं।

कब और कैसे खिलाएं ठोस आहार

जब बच्चा 6 महीने का पूरा हो जाए, तो उसको ठोस आहार खिलाना शुरूकर देना चाहिए। बच्चों की डाइट में आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। ठोस आहार में आप उन्हें आयरन-फोर्टिफाइड अनाज, जैसे- जई, चावल या जौ आदि खिला सकते हैं। इसके अलावा फलों में आप केला, नाशपाती और सेब आदि डाइट में शामिल कर सकते हैं। बता दें कि इस तरह का खाना पचने में आसान होते हैं और इस तरह की डाइट से एलर्जी की भी संभावना कम होती है। बच्चों को खाद्य पदार्थ खिलाने के लिए छोटी मात्रा से शुरूआत करें। फिर धीरे-धीरे यह मात्रा बढ़ाएं। इसके साथ ही बच्चों पर भी नजर रखनी चाहिए कि उनको किसी तरह के एनर्जी के लक्षण तो नहीं हैं।

क्या आपके दोस्त या परिजन मानसिक समस्याओं से गुजर रहा है?

अगर आपका कोई दोस्त या परिजन मानसिक समस्याओं के जूझस रहा है, तो आप उसे इस तरह से इन टिप्स के जरिए मदद कर सकते हैं। साइकोथेरेपिस्ट और लाइफ कोच एम.डी डॉ चांदनी तुगनैत से जानें मानसिक समस्या से कैसे निकले। तो आप इन तरीकों से बाहर लाने में उनकी मदद जरुर करें।

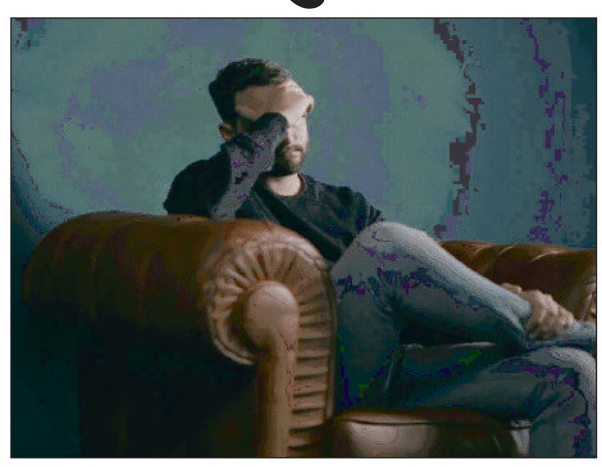

खराब लाइफस्टाइल और भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव होना आम बात है। आजकल हर उम्र के लोगों में तनाव देखने को मिल रहा है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक तनाव की समस्या से परेशान है। वहीं बच्चे आज के प्रतिस्पर्धा वाली पढ़ाई और भविष्य को लेकर चिंता करते हैं। वहीं युवाओं में नौकरी को लेकर काफी तनाव रहता है। कोई इस तनाव से बचने के लिए नया जीवन जीने की कोशिश करता है, तो किसी के मन में आत्महत्या करने का विचार आने लगता है। अगर आपका दोस्त या परिजन तनाव से गुजर रहा है, तो आप इन तरीकों से बाहर लाने में उनकी मदद जरुर करें। साइकोथेरेपिस्ट और लाइफ कोच, एनएलपी स्पेशलिस्ट, हीलर, संस्थापक और निदेशक-गेटवे ऑफ हीलिंग की एम.डी डॉ चांदनी तुगनैत से जानें इस समस्या से कैसे निकले।

उनकी परेशानी को जानने की कोशिश करें

अगर आपका कोई करीबी या दोस्त मानसिक समस्याओं से परेशान हैं या उसके मन में बार-बार सुसाइड करने का ख्याल आता है, तो आप उनसे बात करें उनकी समस्या जानने की कोशिश करें। इसके बाद उनकी समस्या का हल निकालने का प्रयास करें। इससे आपके दोस्त या परिजन को सहारा मिलेगा।

योगा और मेडिटेशन करने को कहें

योग और मेडिटेशन करने से मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग बनती है। मेडिटेशन करने से स्ट्रेस और तनाव कम होता है। तनाव कम होने से समस्या दूर हो जाती है। तो सुसाइड के विचार खुद ही दूर हो जाते हैं।

हॉबीज पर ध्यान दें

डॉ चांदनी तुगनैत के मुताबिक, सुसाइड के विचार को दूर करने के लिए आप पीड़ित व्यक्ति के हॉबीज को जानकर, उन्हें कामों को करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वहीं डांस, पेंटिंग और सिंगिंग करने से तनाव कम होता है।

साइकोथेरेपिस्ट और हीलर से बातचीत करें

अगर आपका कोई करीबी सुसाइड करने का विचार कर रहा है, तो ऐसे में आपको उन्हें साइकोथेरेपिस्ट से मिलने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। क्योंकि साइकोथेरेपिस्ट उनकी मानसिक स्थिति को समझकर ऐसे विचारों को काबू करने की कोशिश करते हैं।

पति के धन पर पत्नी का कितना हक? कानूनी एंगल से आपको जाननी चाहिए यह जरूरी बात

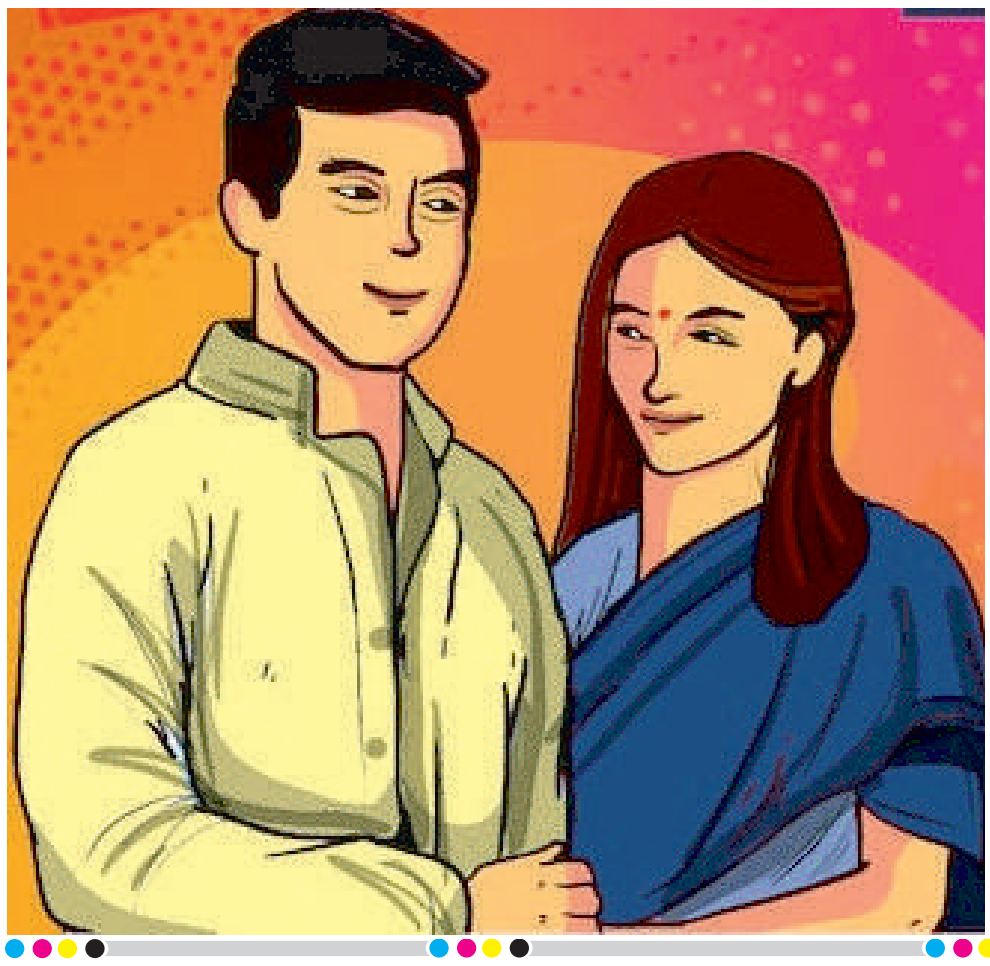

भारत में घर की महिलाएं आमतौर पर पारंपरिक रूप से वित्तीय मसलों से दूर ही रखी जाती हैं. ऐसे में वे अपने वित्तीय अधिकारों (Financial Rights) के बारे में नहीं जान पातीं. इस बाबत उन्हें जागरुक करने की आसपास की उनकी दुनिया में न तो जरूरत महसूस की जाती है और न ही वे खुद आवश्यकता महसूस करती हैं कि उन्हें इस बारे में भागदौड़ कर समझ हासिल करनी चाहिए. लेकिन वक्त बदला है. हम जानते हैं कि महिलाओं को आर्थिक रूप से न सिर्फ आत्मनिर्भर होना जरूरी है बल्कि अपने अधिकारों के बारे में भी जानना जरूरी है. इस दिशा में हमने कानूनी मामलों के जानकारों से बात की और रिसर्च की. आमतौर पर हम महिलाओं के प्रापर्टी में अधिकार के कोण से ही बात करते हैं लेकिन क्या आप जानती हैं कि वित्त से जुड़ी कुछ और जरूरी बातें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए. पत्नी होने के नाते आपके क्या कानूनी अधिकार हैं. तलाक या जीवनसाथी की रोग-दुर्घटनावश मृत्यु हो जाने पर सबकुछ उथल पुथल हो जाता है, ऐसे में आप जागरूक रहेंगी तो वक्त जरूरत पर हालात को बेहतरी से संभाल पाएंगी।

सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसरत वकील और नेशनल कमिशन फॉर वीमन (NCW) की पूर्व सदस्य डॉक्टर चारू वलीखन्ना कहती हैं कि बहुत जरूरी है कि सभी महिलाओं, खासतौर से ऐसी महिलाएं जो कामकाजी नहीं हैं और घर में रहती हैं, को पता होना चाहिए कि आपके पति के क्या क्या फाइंशनल एसेट हैं. वह बताती हैं कि पति के हर फाइनेंशल अलोकेशन, ऐसेट जैसे कि डीमैट, सेविंग खाते, सेविंग स्कीम व अन्य निवेशों में नॉमिनी के तौर पर आपका नाम हो सकता है. बैंक आदि वित्तीय संस्थान आजकल खाता खोलते समय नॉमिनी भरवाती हैं. इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए. ध्यान दें कि नॉमिनी आप बाई- डिफॉल्ट नहीं होतीं बल्कि इसके लिए फॉर्म में पति को बाकायदा नाम और संबंध मेंशन करना होता है. यह भी हो सकता है कि एसेट मालिक बेटे, बेटी या बहू के नाम को किसी एसेट विशेष में नॉमिनी के तौर पर भरे।

यदि आप ही अधिकतर या सभी एसेट में नॉमिनी हैं तो भी केवल इन फाइनेंशनल एसेट में आपका नाम बतौर नॉमिनी होना ही काफी नहीं है. यदि इस एसेट के ओनर की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो महज नॉमिनी होने के कारण आपको इसका डिफॉल्ट हकदार नहीं मान लिया जाएगा यदि इस एसेट की वैल्यू 2 लाख रुपये से ज्यादा है. नॉमिनी भर होने से ऐसी सिचुएशन में यह रकम पत्नी के नाम पर ट्रांसफर नहीं होगी. चारू बताती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, ऐसी विल जो दो गवाहों की मौजूदगी में साइन की गई हो, वह स्वीकार्य होती है. साथ ही, ओनर की

रजिस्टर्ड विल (वसीयत) में आपका नाम होना जरूरी है ताकि एसेट आपके नाम पर ट्रांसफर होने में दिक्कत न हो. चारू वसीयत के रजिस्टर होने पर सर्वाधिक जोर देती हैं. (ये जरूर पढ़ें- लड़कियां झिझकें नहीं, निवेश शुरू करें, पैसा डूबेगा नहीं, हाई रिटर्न देंगे ये 3 विकल्प)

ऐसे में सवाल होता है कि नॉमिनी क्यों लिखवाया जाता है और उसके क्या लाभ या नुकसान हैं.. तो डॉक्टर चारू बताती हैं कि नॉमिनी होना कानूनी रूप से उत्तराधिकारी होना नहीं है. जहां भी नॉमिनी के तौर पर किसी का नाम लिखा है वह केवल ट्रस्टी ही माना जाता है. उत्तराधिकार अधिनियम (या वसीयत) के अनुसार, संपत्ति/संपत्ति के कानूनी उत्तराधिकारी की स्थापना तक, नामांकित व्यक्ति केवल अस्थायी अवधि के लिए ट्रस्टी/संरक्षक होगा. (महिलाओं और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए आप यहां क्लिक कर सकती हैं)

ऐसे में जरूरी है कि पत्नियां अव्वल तो पति के फाइनेंशल एसेट को लेकर सूचित रहें. साथ ही, पति रजिस्टर्ड वसीयत में उत्तराधिकारी को लेकर स्पष्ट रूप से लिखवाए. पति यह भी लिखवा सकता है कि मेरे सभी नॉमिनी (पत्नी/बेटा या बेटी) कानूनी उत्तराधिकारी भी माने जाएं. बता दें कि ऐसा न होने पर कानूनी रूप से पत्नी को कोर्ट में Succesion Certificate जमा करवाना होगा और लंबे प्रोसेस के बाद NoC आदि विभिन्न प्रोसीजर पूरे करने के बाद कोर्ट जब क्लियरेंस देगा, तब ही आप इन ऐसेट की हकदार हो पाएंगी।

"पर्यावरण पाठशाला: ग्रीन कैनोपी पहल: दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर बदलाव के बीज बोना" : अंकुर

दिल्ली एनसीआर की चिलचिलाती गर्मी में, जहां कंक्रीट के जंगल परिदृश्य पर हावी हैं, हरियाली की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। सड़कों और निर्माण परियोजनाओं के निरंतर विस्तार के कारण कई पेड़ों की कटाई हुई है, जिससे विशाल क्षेत्र बंजर हो गए हैं और भीषण गर्मी की चपेट में आ गए हैं। चूंकि इस क्षेत्र पर गर्म हवाओं का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए यह जरूरी है कि हम लोगों पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करें, खासकर फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे इलाकों में, जहां पुराने पेड़ों के नुकसान को काफी हद तक महसूस किया गया है।

इस तत्काल आवश्यकता को पहचानते हुए, पर्यावरण पाठशाला: इंडियन ग्रीन बडी अभियान ने सड़कों के किनारे उन क्षेत्रों की पहचान करने के मिशन पर काम शुरू किया है जो हरित छतरी के विकास के लिए उपयुक्त हैं। उद्देश्य स्पष्ट है: ऐसे पेड़ लगाना जो न केवल छाया प्रदान करेंगे और चिलचिलाती धूप से राहत देंगे बल्कि पर्यावरण की समग्र भलाई में भी योगदान देंगे।

अभियान में वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने के लिए पृथ्वी दिवस से शुरू होकर पर्यावरण दिवस तक एक ठोस प्रयास का प्रस्ताव है। इस अवधि के दौरान, व्यक्तियों, समुदायों, आरडब्ल्यूए और संगठनों को आगे आकर इस नेक प्रयास में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यहां तक कि सिर्फ एक पेड़ लगाने से भी लंबे समय में महत्वपूर्ण अंतर आ सकता है, क्योंकि यह एक हरे-भरे छत्र की नींव रखता है जो आने वाली पीढ़ियों तक पनपेगा।

हालाँकि, यह स्वीकार करना आवश्यक है कि हरे-भरे परिदृश्य की ओर यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं है। पेड़ लगाना सिर्फ पहला कदम है; इसे परिपक्वता तक पोषित करने के लिए समर्पण, दृढ़ता और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। एक पौधे को छाया और आश्रय प्रदान करने में सक्षम मजबूत पेड़ बनने में दो से तीन साल लग सकते हैं। फिर भी, ऐसे प्रयासों के प्रतिफल अथाह हैं, क्योंकि वे सभी के लिए एक स्वस्थ, अधिक टिकाऊ वातावरण में योगदान करते हैं।

इस पहल की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सहयोग महत्वपूर्ण है। परिवहन विशेष, ग्लोबल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ, प्रशासन विभाग के साथ सड़क सुरक्षा टीम

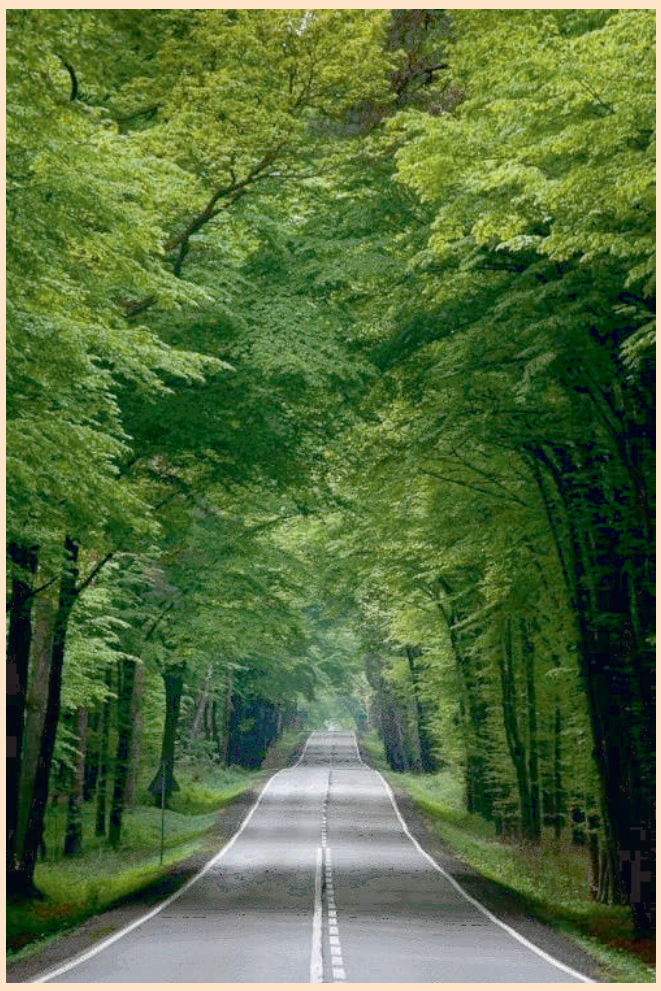

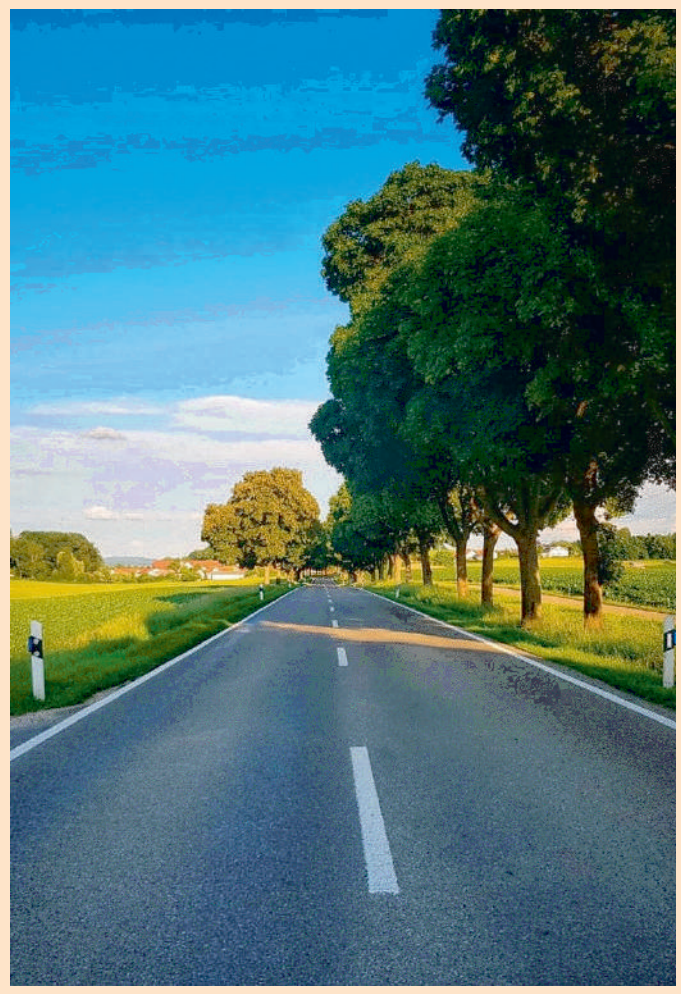

वृक्षारोपण अभियान को सुविधाजनक बनाने और पेड़ों और यात्रियों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एक साथ काम करके, हम सड़क के बंजर हिस्सों को हरियाली के जीवंत गलियारों में बदल सकते हैं, जिससे न केवल सौंदर्य अपील बल्कि क्षेत्र की पारिस्थितिक लचीलापन भी बढ़ेगा।

ग्रीन कैनोपी पहल शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के बीच आशा की किरण का प्रतिनिधित्व करती है। यह प्रत्येक नागरिक के लिए पर्यावरण का संरक्षक बनने, दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर बदलाव के बीज बोने और देखभाल और करुणा के साथ उनका पालन-पोषण करने के लिए कार्रवाई का आह्वान है। आइए हम सब मिलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थिरता और पर्यावरण पाठशाला बनाएं।

indiangreenbuddy@gmail.com

दिल्ली विश्वविद्यालय में 25 अप्रैल से शुरू होगी PG के लिए दाखिले की दौड़, 82 विषयों में होगा नामांकन

दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर (पीजी) में दाखिले की प्रक्रिया 25 अप्रैल से शुरू होगी। डीयू स्नातकोत्तर में इस वर्ष 82 विषयों को छात्र प्रवेश के लिए चुन सकते हैं। पिछले वर्ष 77 विषयों को चुना जा सकता था। इस वर्ष एमए हिंदू स्टडीज एमए चाइनीज एमए कोरियन मास्टर्स - पब्लिक हेल्थ और मास्टर्स- फाइन आर्ट के कोर्स इसमें जोड़े गए हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर (पीजी) में प्रवेश के लिए दाखिले की दौड़ 25 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। डीयू 82 विषयों में प्रवेश के लिए सामान्य सीट आवंटन प्रणाली (सीएसएएस) पोर्टल की शुरुआत करेगा। सीयूईटी परीक्षा देने वाले छात्र पोर्टल पर पंजीकरण करा सकेंगे।

इसके साथ ही पिछले साल शुरू किए गए बीटेक और पांच वर्षीय विधि कार्यक्रम के प्रवेश भी शुरू हो जाएंगे। बीटेक में प्रवेश जेईई मेन के अंकों और विधि कार्यक्रम में प्रवेश क्लेट के अंकों के आधार पर होंगे।

कई नए कोर्सेज किए गए शुरू: कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने बताया कि डीयू स्नातकोत्तर में इस वर्ष 82 विषयों को छात्र प्रवेश के लिए चुन सकते हैं। पिछले वर्ष 77 विषयों को चुना जा सकता था। इस वर्ष एमए हिंदू स्टडीज, एमए चाइनीज, एमए कोरियन, मास्टर्स - पब्लिक हेल्थ और मास्टर्स- फाइन आर्ट के कोर्स इसमें जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि पीजी प्रवेश के लिए आवेदन 25 मई तक किए जा सकेंगे। इसके बाद प्रवेश का दूसरा चरण शुरू होगा। डीयू की डीन एडमिशन प्रो. हनीत गांधी ने 2024-25 के लिए दाखिलों पर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष स्नातकोत्तर के लिए (एनसीवेब सहित) कुल 13500 सीटों पर प्रवेश लिए जा रहे हैं।

250 रुपये शुल्क देकर पंजीकरण कराना होगा: उन्होंने कहा कि सीयूईटी परीक्षा के स्कोर एनटीए की ओर से विश्वविद्यालय को सीधे मिल जाएंगे। छात्रों को सीएसएएस पोर्टल पर 250 रुपये शुल्क देकर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। जिन छात्रों ने कॉलेज में प्रवेश ले लिया होगा और वे प्रवेश वापस लेंगे तो एक हजार रुपये फीस अदा कर वे प्रवेश वापस ले सकेंगे। उनकी जमा की गई फीस वापस कर दी जएगी। छात्रों को पोर्टल पर कालेज और कोर्स के विकल्प भरने होंगे। जितने वे कॉलेज व कोर्स के विकल्प भरेंगे, उतना उनके लिए प्रवेश आसान होगा।

जेईई मेन के स्कोर के आधार पर प्रवेश: उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष बीटेक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसमें इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग की शुरुआत की गई है। तीनों ब्रांच में 120-120 सीटों पर प्रवेश दिए जा रहे हैं। जईई मेन के स्कोर के आधार पर छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा।

इसके अलावा बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी के लिए प्रत्येक में 60-60 सीटों पर दाखिले किए जाएंगे। सभी बीटेक और विधि कार्यक्रम के लिए फीस पिछले वर्ष की तरह होगी। छात्रों को डीयू की ओर से घोषित सभी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा।

'अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की साजिश, इसमें LG सक्सेना भी शामिल'; मंत्री आतिशी का गंभीर आरोप

परिवहन विशेष न्यूज

आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने इंसुलिन देने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका के विरोधमें दो वकील आए। यह वकील हैं योगेंद्र हांडू और बानी दीक्षित। ये दोनों वकील जेल प्रशासन की तरफ से कोर्ट में पेश हुए। ये दोनों वकील LG कार्यालय के स्पेशल काउंसिल हैं। इससे साबित होता है कि इस साजिश में LG कार्यालय भी शामिल है।

नई दिल्ली। सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में इंसुलिन न दिए जाने को लेकर आप ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में कोर्ट में याचिका भी दायर की थी, जिस पर आज राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और इसपर सोमवार को फैसला आएगा। वहीं दिल्ली की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है।

आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने इंसुलिन देने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका के विरोधमें दो वकील आए। यह वकील हैं योगेंद्र हांडू और बानी दीक्षित। ये दोनों वकील जेल प्रशासन की तरफ से कोर्ट में पेश हुए। ये दोनों वकील LG कार्यालय के स्पेशल काउंसिल हैं। इससे साबित होता है कि इस साजिश में LG कार्यालय भी शामिल है।

पीएम मोदी अंग्रेजों की तरह क्रूरता कर रहे: आतिशी

उन्होंने कहा कि जैसे आजादी से पहले अंग्रेज जेल में भगत सिंह के साथ क्रूरता करते थे, वैसे ही आज नरेंद्र मोदी की BJP सरकार अपने विरोधी नेताओं के साथ कर रही है। BJP और नरेंद्र मोदी सरकार का राजनैतिक हथियार ED है। ED का काम मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच करना होता है। यहां ED अरविंद केजरीवाल के खाने पर सवाल उठा रही है। क्या उनके खाने में पैसे छुपाए हुए थे?

"गुरुग्राम फ़रीदाबाद टोल दुविधा"

परिवहन विशेष न्यूज

हर दिन, फ़रीदाबाद और गुरुग्राम के बीच सड़क का विस्तार यात्रियों के लिए युद्ध का मैदान बन जाता है, जिसमें गंभीर भीड़भाड़ और सुस्त यातायात आम बात हो गई है। यह बाधा न केवल ड्राइवरों के धैर्य की परीक्षा लेती है बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है। टोल अधिकारियों से बार-बार समाधान लागू करने का आग्रह किया गया है, फिर भी ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है।

पिछले साल, विशेषकर पीक आवर्स के दौरान भीड़भाड़ को कम करने के लिए एक टैग प्रणाली के कार्यान्वयन के संबंध में वादे किए गए थे। हालाँकि, जैसे-जैसे हम एक और वर्ष के करीब आ रहे हैं, ये आश्वासन ठोस परिणामों में तब्दील नहीं हुए हैं। संबंधित अधिकारियों की ओर से आधिकारिक बयान की कमी यात्रियों की निराशा को बढ़ाती है।

इन चुनौतियों के मद्देनजर, टोल अधिकारियों के लिए यह जरूरी है कि वे व्यस्ततम कार्यालय समय के दौरान सुचारू यातायात प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्याप्त जनशक्ति तैनात करें। इसके अतिरिक्त, व्यापक यातायात प्रबंधन रणनीतियों को तैयार करने के लिए यातायात अधिकारियों और हितधारकों के साथ सहयोग आवश्यक है।

गुरुग्राम फ़रीदाबाद टोल रोड की समस्याएँ कई और विविध हैं। टैग प्रणाली के अभाव से लेकर धीमी गति से यातायात की गति से लेकर ज़िगज़ैगिंग ओवरटेक की खतरनाक प्रथा तक, प्रत्येक चुनौती सड़क पर अराजकता में योगदान करती है। इसके अलावा, आवारा मवेशियों की

मौजूदगी और अपर्याप्त स्ट्रीट लाइटिंग स्थिति को और खराब कर देती है, जिससे यात्रियों के लिए गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा हो जाते हैं।

जैसा कि हम समाधान के लिए प्रयास करते हैं, दैनिक यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और सुविधाओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है। क्या मार्ग में ड्राइवरों के लिए पर्याप्त विश्राम क्षेत्र, आपातकालीन सेवाएं और सुविधाएं हैं? समग्र आवागमन अनुभव को बढ़ाने और सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन चिंताओं को दूर करना सर्वोपरि है।

टोल रोड की भीड़ न केवल यात्रियों के धैर्य की परीक्षा लेती है बल्कि इसके महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव भी होते हैं। तनाव के स्तर में वृद्धि, समय की बर्बादी और दुर्घटनाओं के बढ़ते जोखिम इसके कुछ ही परिणाम हैं। इसके अलावा, लंबे समय तक भीड़भाड़ के आर्थिक प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, उत्पादकता में कमी और ईंधन की बढ़ती खपत का असर व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों पर पड़ता है।

अंत में, गुरुग्राम फ़रीदाबाद टोल रोड की दुर्दशा सभी हितधारकों से तत्काल ध्यान देने और ठोस प्रयासों की मांग करती है। प्रभावी यातायात प्रबंधन रणनीतियों को लागू करके, सड़क सुरक्षा पहलों को प्राथमिकता देकर और यात्री सुविधाओं को बढ़ाकर, हम भीड़भाड़ को कम कर सकते हैं और सभी के लिए एक सुरक्षित, अधिक कुशल यात्रा अनुभव बना सकते हैं।

सड़क सुरक्षा ओमनी फाउंडेशन

'आम आदमी आम नहीं तो क्या मशरूम खाएगा?', केजरीवाल की डाइट पर कोर्ट में वकीलों ने दी दलीलें; सोमवार तक फैसला सुरक्षित

परिवहन विशेष न्यूज

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंह सिंघवी ने तर्क दिया कि उनका मुवक्किल 22 वर्षों से मधुमेह से पीड़ित है जिसके लिए उसे प्रतिदिन इंसुलिन की आवश्यकता होती है। उनकी गिरफ्तारी 21 मार्च को हुई है। उसके बाद यह सामान्य आधार है जिसका वो पालन करने में असमर्थ हैं। सिंघवी ने केजरीवाल के शुगर लेवल की निगरानी करने वाले चार्ट का हवाला दिया।

नई दिल्ली। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल के अंदर इंसुलिन देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी पर फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।

स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि वह इस पर फैसला 22 अप्रैल को सुनाएगी। हालांकि इस दौरान उन्होंने तिहाड़ जेल और ईडी को कल इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा। इससे पहले, केजरीवाल के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल की नए आवेदन की कॉपी ईडी को मुहैया करा दी गई है।

22 वर्षों से मधुमेह से पीड़ित हैं केजरीवाल: सिंघवी

सिंघवी ने तर्क दिया कि उनका मुवक्किल 22 वर्षों से मधुमेह से पीड़ित है, जिसके लिए उसे प्रतिदिन इंसुलिन की आवश्यकता होती है। उनकी गिरफ्तारी 21 मार्च को हुई है। उसके बाद, यह सामान्य आधार है जिसका वो पालन करने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मुवक्किल बार-बार कह रहा है कि उनका डॉक्टर शुगर लेवल की निगरानी कर

सकता है, इसकी लगातार निगरानी होनी चाहिए। सिंघवी ने केजरीवाल के शुगर लेवल की निगरानी करने वाले चार्ट का हवाला दिया।

सिर्फ तीन बार आम केजरीवाल को भेजे गए: सिंघवी

सिंघवी ने ईडी के आम खानेवाले बयान पर कहा कि केजरीवाल को जेल में सिर्फ तीन बार आम भेजे गए। आठ अप्रैल के बाद कोई आम नहीं भेजा गया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने चाय के साथ चीनी का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी चाय में शुगर फ्री का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो मधुमेह रोगी हूं। ईडी ने आलू-पूरी खाने का आरोप लगाया। सिंघवी ने कहा ये सरासर गलत आरोप है। 48 बार भेजे गए भोजनों में केवल एक बार केजरीवाल ने नवरात्र प्रसाद के रूप में आलू पूरी खाई।

एक कैदी के रूप में स्वास्थ्य का अधिकार नहीं: सिंघवी

सिंघवी ने कहा कि मैं अदालत से जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध कर रहा हूं कि पर्याप्त उपचार उपलब्ध कराया जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं एक कैदी हूं, मुझे स्वास्थ्य का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या मेरा मुवक्किल गैंगस्टर है? क्या वह कट्टर अपराधी है कि उन्हें अपने डॉक्टर के साथ रोजाना 15 मिनट की वीसी नहीं मिल सकती।

केजरीवाल के एक अन्य वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि मैं पहली बार देख रहा हूं कि जेल अधिकारियों की तरफ से भी विशेष अधिवक्ता उपस्थित हैं। आम आदमी ही आम खा रहा है। आम आदमी आम नहीं खाएगा तो क्या मशरूम खाएगा?

डॉक्टरों ने कई चीजें खाने से मना किया: ईडी

ईडी की तरफ से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि केजरीवाल के लिए निर्धारित आहार देखें। इसमें किसी मिठाई या फल या मीठी वस्तु का कोई संदर्भ नहीं है। इसी आधार पर यह प्रस्तुतिकरण किया गया है। उस सीमित प्रस्तुतिकरण पर रिपोर्ट मंगाई गई। आप एक बार अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित आहार देखें। देखकर ही समझ आता है कि इसमें बहुत सी चीजें प्रतिबंधित हैं।

मेडिकल बोर्ड को जांच करने दीजिए: ईडी

हुसैन ने कहा कि प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर अब कुछ वर्षों से केजरीवाल का इंसुलिन लेना बंद हो गया है। जब केजरीवाल डॉक्टर से मिले तो उन्होंने खुद यह बात कही। इस पर सिंघवी ने कहा- नहीं, नहीं। फरवरी 2024 में आखिरी बार ली थी। तब ईडी ने कहा- क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं? न तो सिंघवी और न ही मैं विशेषज्ञ हैं। एम्स के डॉक्टरों को विचार करने दीजिए। याचिकाकर्ता कैसे विचार कर सकता है? एक मेडिकल बोर्ड को जांच करने दीजिए कि केजरीवाल को किस चीज की जरूरत है।

कानूनी मुलाकातों का हुआ दुरुपयोग: ईडी

इस पर सिंघवी ने कहा- स्वास्थ्य मेरा अधिकार है। मैं 15 मिनट की वीसी मांग रहा हूं। मैं मेडिकल जमानत या अस्पताल में इलाज की मांग नहीं कर रहा हूं। इस पर ईडी ने कहा कि कानूनी मुलाकातों का पहले भी दुरुपयोग किया गया है। मुझे समझ नहीं आता कि वो स्वतंत्र जांच के लिए क्यों कतरा रहे हैं? वे ऐसी रिपोर्टें तैयार कर रहे हैं जो विशेषज्ञों की राय के अनुरूप नहीं हैं। कोई भी डॉक्टर इन खाद्य पदार्थों का सेवन करने के लिए नहीं कहेगा। कोई विशेष उपचार तब तक नहीं दिया जाना चाहिए, जब तक यह न दिखाया जाए कि जेल के अंदर उपचार नहीं दिया जा रहा है।

अगले 2-3 दिनों में गर्मी दिखाएगी तेवर, अप्रैल अंत तक 40 के पार जाएगा पारा; मई-जून में 45 डिग्री...

वेदर फोरकास्ट एनसीआर सहित उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ से मिल रही राहत का दौर खत्म होने को है। तीन दिन की राहत के बाद अब गर्मी बढ़ेगी और इस महीने के अंत यानी अप्रैल के आखिर तक पारा 40 डिग्री के पार जा सकता है। वहीं आईएमडी का तो यह भी अनुमान है कि मई में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है।

नई दिल्ली। मार्च के बाद अप्रैल भी धीरे धीरे खत्म होने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अधिकतम तापमान अभी भी नियंत्रण में ही है।

थोड़े-थोड़े अंतराल पर एक के बाद एक आ रहे पश्चिमी विक्षोभों ने अबकी बार गर्मी की चुभन को अभी तक बढ़ने नहीं दिया है। लेकिन अब यह राहत बहुत लंबी नहीं चलने वाली। सिर्फ दो तीन दिन के बाद गर्मी ही नहीं, तापमान में भी वृद्धि होने लगेगी। मई एवं जून खासी तपिश भरे हो सकते हैं।

मौसम विज्ञानियों का कहना है कि एनसीआर सहित उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ से मिल रही राहत का दौर समाप्त होने को है।

मई में 45 डिग्री के पार पहुंचेगा पारा

आजकल में एक और पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्रों पर दस्तक दे रहा है। दो तीन दिन इसका असर उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों पर भी नजर आएगा 22 अप्रैल से गर्मी और तापमान में वृद्धि होने लगेगी।

माह के अंत तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री पार हो जाएगा तो मई में इसके 45 डिग्री पार चले जाने के आसार हैं।

विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार अप्रैल में अपेक्षाकृत पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा आए, लेकिन इसकी कोई खास वजह नहीं है, पश्चिमी विक्षोभों के घटने-बढ़ने का क्रम ऐसे ही चलता रहता है।

देश के अधिकांश हिस्से में सामान्य से अधिक तापमान रिकॉर्ड किए जाने की संभावना

मौसम विभाग का अनुमान है कि भारत में इस साल गर्मी के मौसम (अप्रैल से जून) में औसत से अधिक गर्मी के दिन देखने को मिलेंगे। देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है।

अनुमान है कि गर्मी का सर्वाधिक असर दक्षिणी हिस्से, मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर-पश्चिमी मैदानी इलाकों पर पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि देश के मैदानी इलाके इस बार हर साल से ज्यादा तपने वाले हैं।

मतदाता असली है या फर्जी दो रुपये में चलेगा पता, चुनाव आयोग ने कर रखी है जबरदस्त तैयारी

परिवहन विशेष न्यूज

फर्जी मतदाता का दावा करने वाले पोलिंग एजेंट व अन्य लोग को पीठासीन अधिकारी से संपर्क करना होगा। पीठासीन अधिकारी मतदाता से उसका नाम पिता का नाम पता घर में कितने वोटर हैं आदि कई बिंदुओं के बारे में पूछताछ करेगा। संतुष्टि न होने पर वह सच और झूठ की पहचान करने के लिए क्षेत्र के पार्षद या प्रधान को बुलाकर मतदाता के बारे में गवाही लेगा।

गाजियाबाद। गौतमबुद्ध नगर लोकसभा में दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को करीब 26 लाख 75 हजार मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।

मतदान के दिन मतदान केंद्र पर अक्सर फर्जी मतदाता की शिकायतें पोलिंग एजेंट से लेकर अन्य लोग करते हैं। चुनाव आयोग ने मतदान के दिन फर्जी मतदाता पहचानने के लिए गाइडलाइन जारी की हैं।

इसमें व्यवस्था की गई है कि किसी भी प्रत्याशी का एजेंट फर्जी मतदाता का पता लगाने के लिए दो रुपये की रसीद कटवाकर उसे चैलेंज कर सकता है। दो रुपये खर्च करने पर पता चल जाएगा कि मतदाता असली है या फर्जी।

फर्जी मतदाता का दावा करने वाले को पीठासीन अधिकारी से करना होगा संपर्क

फर्जी मतदाता का दावा करने वाले पोलिंग एजेंट व अन्य लोग को पीठासीन अधिकारी से संपर्क करना होगा। पीठासीन अधिकारी मतदाता से उसका नाम, पिता का नाम, पता, घर में कितने वोटर हैं आदि कई बिंदुओं के बारे में पूछताछ करेगा।

संतुष्टि न होने पर वह सच और झूठ की पहचान करने के लिए क्षेत्र के पार्षद या प्रधान को बुलाकर मतदाता के बारे में गवाही लेगा।

यदि मतदाता यह साबित कर दे कि वही असली मतदाता है, तो उसे वोट डालने का मौका मिलेगा और अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे फर्जी मतदाता मानकर उसके खिलाफ केस दर्ज कराया जा सकता है।

टेंडर बैलेट पत्र का भी लें सकते हैं सहारा

यदि कोई मतदाता केंद्र पर अपना वोट डालने पहुंचता है, लेकिन उससे पहले ही कोई उसके नाम से वोट डाल चुका होता है तो वह टेंडर वोट का सहारा ले सकता है। इसके लिए उसे पीठासीन अधिकारी के पास जाना होगा। यदि मतदाता सूची में नाम होगा तो पीठासीन अधिकारी एक प्रपत्र पर मतदान कराते हैं।

इसके बाद उस मतपत्र को लिफाफे में बंद कर देते हैं। मतगणना के समय कम वोट के अंतर से हार-जीत की स्थिति में ऐसे वोट की गणना की जाती है। इसे टेंडर वोट कहते हैं।

पीठासीन अधिकारियों को मतदान के समय मिलने वाले किट में टेंडर बैलेट पत्र दिए जाते हैं और चुनाव अधिकारियों को मतदान खत्म होने के बाद इसका ब्योरा आयोग को देना होता है। ये वोट बैलेट पेपर से पड़ते हैं।

'चौधरी चरण सिंह के सपनों को साकार कर रही मोदी सरकार', बागपत में चुनावी रैली के दौरान बोले सीएम योगी

परिवहन विशेष न्यूज

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चाहे पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए अन्नदाताओं का सम्मान हो या भारत को दुनिया में सम्मान दिलाने का कार्य ये तमाम योजनाएं नये भारत की पहचान बन रही हैं। सीएम योगी शुक्रवार को मोदीनगर में बागपत लोकसभा सीट के लिए एनडीए प्रत्याशी डॉ राजकुमार सांगवान के समर्थन में विशाल चुनावी जनसभा की।

गाजियाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अन्नदाता किसानों का सम्मान और उत्थान करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के सपनों को साकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अन्नदाताओं के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की, जिसका परिणाम हम सबके सामने है।

उन्होंने कहा कि चाहे पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए अन्नदाताओं का सम्मान हो, या भारत को दुनिया में सम्मान दिलाने का कार्य, ये तमाम योजनाएं नये भारत की पहचान बन रही हैं।

सीएम योगी शुक्रवार को मोदीनगर में बागपत लोकसभा सीट के लिए एनडीए प्रत्याशी डॉ राजकुमार सांगवान के समर्थन में विशाल चुनावी जनसभा की।

लोगों में उतावलापन दिख रहा

उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए मतदान चल रहा है। वोटिंग की स्पीड बताती है कि देश में फिर एक बार मोदी सरकार लाने के लिए लोगों में उतावलापन दिख रहा है।

ऐसा होना लाजमी है क्योंकि जो हमारे पूर्वजों को सम्मान दें उनका सम्मान होना ही चाहिए। पहली बार चौधरी साहब को मोदी जी ने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर हमारे यूपी का गौरव बढ़ाया है।

गिनाई उपलब्धियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत 80 करोड़ लोगों को 4 साल से फ्री में राशन दे रहा है, वहीं भारत से अलग हुए पाकिस्तान में 23 करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं। जब हम अच्छा नेता चुनते हैं तो परिणाम भी अच्छा आता है।

आज 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा चुका है, 50 करोड़ जनता का जनधन अकाउंट खुल चुका है, 12 करोड़ अन्नदाताओं को किसान सम्मान निधि और 12 करोड़ घरों में शौचालय के साथ ही 10 करोड़ माताओं को उज्ज्वला योजना से लाभान्वित किया जा चुका है।

श्रीराम के सूर्य तिलक ने पूरे देश को गौरवान्वित किया

मुख्यमंत्री ने रामनवमी के अवसर पर भगवान श्रीराम के सूर्य तिलक को लेकर कहा कि इसने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। वहीं उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन पार्टियों ने पश्चिमी यूपी में सुरक्षा के लिए खतरा खड़ा कर दिया था।

न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी, किसान के खेत से उसके ट्यूबवेल ही उखाड़ लिये जाते थे। हमारी सरकार ने 15 लाख निजी नलकूपों को फ्री बिजली देने का प्रावधान किया है।

उन्होंने कहा कि चौधरी साहब के सपने को साकार करने के लिए सरकार ने ये निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें दंगा कराती थीं, आज दंगा और कर्फ्यू नहीं होते, अब तो शानदार तरीके से कांवड़ यात्राएं निकलती हैं।

हमने कह दिया है कि किसी ने बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया तो अपराधी का राम नाम सत्य तय है। सीएम योगी ने कहा कि मजबूत सरकार में ही सुशासन और सुरक्षा का लाभ प्राप्त होता है।

कमल खिलाने के लिए बागपत में नल आवश्यक

सीएम योगी ने कहा कि अबकी बार 400 पार के लिए और मोदी सरकार के लिए बागपत में भी एनडीए के प्रत्याशी विजयी होने चाहिए। डॉ राजकुमार सांगवान जी जैसे कार्यकर्ता को जयंत चौधरी ने जनता की सेवा के लिए उतारा है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद।

एक सामान्य कार्यकर्ता जिसने चौधरी साहब के समय से उनके मूल्यों और आदर्शों पर कायम रहे, उन्हें जिताने और देश में कमल खिलाने के लिए बागपत में नल आवश्यक है। इसके लिए आपको राजकुमार सांगवान बनना पड़ेगा। एक एक वोट को नल चुनाव चिह्न के साथ जोड़ना होगा।

इस अवसर पर रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी, बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येन्द्र सिसोदिया, भाजपा के जिलाध्यक्ष सत्यपाल प्रधान, विधायक मोदी नगर डॉ मंजू सिवाच, जिला पंचायत अध्यक्ष ममता त्यागी, रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी, लोकसभा प्रभारी डॉ अशोक नागर, सांसद मलूक नागर, उमेश राणा, सूरज पाल, भाजपा के प्रदेश मंत्री डॉ चंद्र मोहन, प्रत्याशी डॉ राजकुमार सांगवान सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे।

मां स्कूल में सहायिका... बेटी बनी IAS; तीन बार मिली असफलता पर नहीं मानी हार, चौथी बार में...

परिवहन विशेष न्यूज

बेहद सामान्य परिवार से आने वाली पिंकी पहले तीन प्रयासों में प्रारंभिक परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं कर पाई थी लेकिन वह अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुई और चौथे प्रयास में सफलता 948 वीं रैंक हासिल की। पिंकी अपने परिवार में पहली आईएएस है। रिश्तेदारी में भी दूर तक कोई नहीं है। पिंकी ने बताया कि वह सामान्य परिवार से आती है लेकिन...।

नोएडा। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। महाकवि सोहन लाल द्विवेदी की इन पंक्तियों को नोएडा की सेक्टर-45 काशीराम कॉलोनी में रहने वाली पिंकी मसीह सही मायने में चरितार्थ किया है।

बेहद सामान्य परिवार से आने वाली पिंकी पहले तीन प्रयासों में प्रारंभिक परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं कर पाई थी, लेकिन वह अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुई और चौथे प्रयास में सफलता 948 वीं रैंक हासिल की।

दूर की रिश्तेदारी में भी नहीं है कोई आईएएस

पिंकी अपने परिवार में पहली आईएएस है। रिश्तेदारी में भी दूर तक कोई नहीं है। पिंकी ने बताया कि वह सामान्य परिवार से आती है, लेकिन पढ़ाई को लेकर हमेशा से ही उनके स्वजन ने प्रोत्साहित किया।

उनकी मां फादर एग्नेल स्कूल में सहायिका काम करती हैं और सही मायने में मां के चलते ही उनकी पढ़ाई अच्छी से हो पाई। उन्होंने फादर एग्नेल से ही स्कूली शिक्षा पूरी की।

12वीं में उनके 91 प्रतिशत अंक थे। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से फिजियोथेरेपी में स्नातक प्रवेश लिया। वह विश्वविद्यालय टॉपर रहीं। उसके बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू की, लेकिन यहां पर मेहनत और भाग्य ने उनके धैर्य की पूरी परीक्षा ली।

सी-सैट ने शुरुआत में किया परेशान

पहले तीन प्रयास में सी-सैट के चलते वह प्रारंभिक परीक्षा भी नहीं निकाल पाई, लेकिन मैदान में डटी रही। वह ईमानदारी से प्रयास कर रही थी तो भरोसा था कि सफलता जरूर मिलेगी।

पिंकी का वैकल्पिक विषय मानव विज्ञान था। तैयार कर रहे छात्रों को उनकी यही सलाह है कि पहले अखबार पढ़ना शुरू करें। यहां से करंट अफेयर्स मजबूत होगा।

इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। फिर एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करें। उसके बाद आगे बढ़े। इससे आप का बेस तैयार हो जाएगा।

डॉ. आंबेडकर पुस्तकालय से की तैयारी

पिंकी की तैयारी में दलित उत्थान सेवा समिति की तरफ से सेक्टर-37 डा. भीमराव आंबेडकर पुस्तकालय की भी अहम भूमिका रही। उन्होंने पुस्तकालय में पढ़कर अपनी तैयारी को धार दी।

यहां की पठन सामग्री का उपयोग किया। पुस्तकालय के संरक्षक गणेश जाटव ने बताया कि वह बहुत ही होनहार छात्रा है। उनकी उपलब्धि दूसरे छात्रों को भी प्रोत्साहित करेगी।

बुधवार को पुस्तकालय प्रबंधन ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर बालक राम प्रधान, भीमराज जाटव, पीतम सिंह, राजेंद्र ठेकेदार, सतपाल सिंह, उदय सिंह, कमल सिंह, जगत सिंह, राजकुमार समेत अन्य उपस्थित रहे।

हर्षिता ने बिना कोचिंग हासिल की 214वीं रैंक

सेक्टर-134 जेपी कासमस सोसायटी में रहने वाली हर्षिता शर्मा ने मंगलवार को जारी संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के परिणामों में 214वीं रैंक हासिल की है। उन्होंने ने तीसरे प्रयास में सफलता प्राप्त की है।

मूलतः पंजाब के पटियाला की रहने वाली हर्षिता ने बिना कोचिंग के तैयारी की। साथ ही पहले दो प्रयास में वह प्रारंभिक परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं कर पाई थी। ऐसे में तैयारी कर रहे छात्रों के लिए उनकी उपलब्धि बेहद खास है।

हर्षिता ने बताया कि एनसीईआरटी के साथ अपनी तैयारी शुरू करें और उसके बाद हर विषय की कोई एक प्रामाणिक पुस्तक को पढ़ें। अलग-अलग पुस्तकों की बजाय उसी को बार-बार पढ़े।

युवती के साथ बदतमीजी का विरोध करना अधिवक्ता को पड़ा भारी, आरोपियों ने काट लिए कान

गुरुग्राम के राजीव चौक के पास एक रेस्टोरेंट में युवती के साथ बदतमीजी का विरोध करने पर अधिवक्ता का कान काट लिया। अधिवक्ता ने बताया कि गाली-गलौज होने पर वह रेस्टोरेंट से बाहर आए तो उनके ऊपर तीन युवकों ने डंडों से हमला कर दिया और उनका कान काट लिया। पीड़ित की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

गुरुग्राम। राजीव चौक के पास एक रेस्टोरेंट में युवती के साथ बदतमीजी का विरोध करना अधिवक्ता को भारी पड़ गया। अधिवक्ता का कहना है कि गाली-गलौज होने पर वह रेस्टोरेंट से बाहर आए तो उनके ऊपर तीन युवकों ने डंडों से हमला कर दिया और उनका कान काट लिया। अधिवक्ता की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अधिवक्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह जिला अदालत में प्रैक्टिस करते हैं। बुधवार रात करीब आठ बजे वह अपने दो दोस्तों के साथ राजीव चौक के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में गए थे। रात करीब नौ बजे वहां पर उनकी दो दोस्त भी आ गई थीं।

विरोध करने पर शुरू की गाली-गलौज

उनका आरोप है कि उसी दौरान वहां पर एक युवक उनकी दोस्त के साथ आकर खड़ा हो गया और बदतमीजी करनी शुरू कर दी। उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ उसने गाली-गलौज करनी शुरू कर दी। उसी दौरान एक और युवक वहां पर आ गया था।

सोने की चेन छीनकर कान काट लिया

इसके बाद वह अपनी दोस्त के साथ बाहर आ गए। उनका आरोप है कि जब वह गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो अचानक से दोनों युवकों ने अपने एक अन्य साथी के साथ लाठी-डंडों से उन पर हमला कर दिया। उनका आरोप है कि उनके गले से सोने की चेन भी छीन ली गई और उनका कान काट लिया।

नक्सलवाद: आखिर कब थमेगी अपने ही युवाओं से खून की होली

छत्तीसगढ़ में पिछले 14 सालों के भीतर 1582 नक्सली मुठभेड़ हुई है। इन मुठभेड़ के दौरान 1452 नक्सली मारे गए हैं। इस बीच 1002 आम नागरिकों की भी मौत हुई है। वहीं इन हमलों में 1222 जवान शहीद हो चुके हैं।

योगेन्द्र योगी

छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षाबलों ने 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन के लिए सुरक्षाबलों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। जवान नक्सलियों के अड्डे तक पहुंचने के लिए 20 घंटे तक पैदल चले हैं। नक्सलियों के समूह को देखने के बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू की थी। जब बंदूकें शांत हुईं, तो जंगल के फर्श पर सूखे पत्तों के बीच 29 माओवादी मृत पड़े थे। इनमें ललिता, शंकर और दूसरे कमांडर विनोद गावड़े के शवों की पहचान सबसे पहले की गई। मृतकों में पंद्रह महिलाएं भी थीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खिलाफ मिली सफलता को केन्द्र और राज्य में भाजपा सरकार की उपलब्धि बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बहुत कम समय में देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंका जाएगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद से इस अभियान को गति मिली है। नक्सली इलाकों में सुरक्षा बल कैंप लगाए जा रहे हैं। 19 के बाद इनकी संख्या 250 हो गई है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में छत्तीसगढ़ पुलिस से भी मदद मिल रही है। राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद तीन महीने में 80 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। 125 गिरफ्तार हुए हैं और 150 ने आत्मसमर्पण किया है। देश के 10 राज्यों में 70 जिलों में नक्सलवाद का प्रभाव है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य झारखंड जहां 16 जिले हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित 14 जिले शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ में पिछले 14 सालों के भीतर 1582 नक्सली मुठभेड़ हुई है। इन मुठभेड़ के दौरान 1452 नक्सली मारे गए हैं। इस बीच 1002 आम नागरिकों की भी मौत हुई है। वहीं इन हमलों में 1222 जवान शहीद हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद नक्सलियों को आशंका थी कि सरकार उनके खिलाफ अभियान तेज करेगी और हुआ भी ऐसा ही। राज्य की नई सरकार ने शान्ति का प्रस्ताव भी सामने रखा था लेकिन नक्सल नेताओं की तरफ से इस प्रस्ताव पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और सुरक्षाबलों को बस्तर में फ्री हैण्ड कर दिया गया हैं। ऐसे में पिछले तीन महीनों में नक्सलियों को कई बड़े नुकसान उठाने पड़े हैं। अब तक जहां माओवादियों के बटालियन स्तर के नेता ही ढेर हुए थे तो इस बार शंकर राव जैसे डिवीजन लेवल का नेता पुलिस के गोली का शिकार हुआ हैं। ऐसे में नक्सली प्रदेश में पूरी तरफ से बैकफुट में हैं। अब लगातार सवाल किये जा रहे हैं कि आखिर कब तक छत्तीसगढ़ को इस नक्सल दंश से छुटकारा मिल पायेगा और बस्तर में खून की होली थमेगी। सरकार, सुरक्षा बलों एवं स्थानीय लोगों की संयुक्त कोशिशों का परिणाम है कि पिछले एक दशक में वामपंथी अतिवाद संबंधी घटनाओं, मौतों और उनके भौगोलिक प्रसार में काफी कमी आई है। जहाँ वर्ष 2010 में वामपंथी अतिवाद से प्रभावित ज़िलों की संख्या 96 थी वहीं वर्ष 2018 में प्रभावित ज़िलों की संख्या 60 रह गई है। वर्ष 2009 में जहाँ नक्सलवाद की घटनाओं और इन घटनाओं में मरने वालों की संख्या क्रमश 2258 व 1005 थी वहीं वर्ष 2018 में यह संख्या घटकर क्रमश 833 एवं 240 रह गई। देश के जिन 8 राज्यों के लगभग 60 जिलों में यह समस्या बनी हुई है उनमें ओडिशा के 5, झारखंड के 14, बिहार के 5, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 10, मध्य प्रदेश के 8, महाराष्ट्र के 2 तथा बंगाल के 8 जिले शामिल हैं। वर्ष 2015 के बाद से नक्सलियों के 90 प्रतिशत हमले लगभग चार राज्यों- छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और ओडिशा में हुए हैं।

इसे भी पढ़ें: Chhattisgarh | नक्सलियों की हत्या के बाद छत्तीसगढ़ में कैसा है चुनावी माहौल? CM ने की बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की, बदले की आग में जल रहे माओवादी

माओवादियों के थिंक-टैंक और प्रथम पंक्ति के नेता या तो मारे जा चुके हैं या इस विचारधारा को छोड़ चुके हैं। भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग ज़िले के नक्सलबाड़ी नामक गाँव से हुई और इसीलिये इस उग्रपंथी आंदोलन को 'नक्सलवाद' के नाम से जाना जाता है। ज़मींदारों द्वारा छोटे किसानों के उत्पीडन पर अंकुश लगाने के लिये सत्ता के खिलाफ चारू मजूमदार, कानू सान्याल और कन्हाई चटर्जी द्वारा शुरू किये गए इस सशस्त्र आंदोलन को नक्सलवाद का नाम दिया गया। यह आंदोलन चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग की नीतियों का अनुगामी था। आंदोलनकारियों का मानना था कि भारतीय मज़दूरों और किसानों की दुर्दशा के लिये सरकारी नीतियाँ ज़िम्मेदार हैं। ये लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ हैं और ज़मीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खत्म करने के लिये हिंसा का सहारा लेते हैं। ये समूह देश के अल्प विकसित क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं और लोगों को सरकार के प्रति भड़काने की कोशिश करते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें माओवादी हिंसा को मुख्यत कानून-व्यवस्था की समस्या मानती रही हैं, लेकिन इसके मूल में गंभीर सामाजिक-आर्थिक कारण भी रहे हैं। नक्सलियों का कहना है कि वे उन आदिवासियों और गरीबों के लिये लड़ रहे हैं, जिनकी सरकार ने दशकों से अनदेखी की है। वे ज़मीन के अधिकार एवं संसाधनों के वितरण के संघर्ष में स्थानीय सरोकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। माओवाद प्रभावित अधिकतर इलाके आदिवासी बहुल हैं और यहाँ जीवनयापन की बुनियादी सुविधाएँ तक उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इन इलाकों की प्राकृतिक संपदा के दोहन में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ न सड़कें हैं, न पीने के लिये पानी की व्यवस्था, न शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ और न ही रोज़गार के अवसर। नक्सलवाद के उभार के आर्थिक कारण भी रहे हैं।

नक्सली सरकार के विकास कार्यों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हैं। वे आदिवासी क्षेत्रों का विकास नहीं होने देते और उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काते हैं। वे लोगों से वसूली करते हैं एवं समांतर अदालतें लगाते हैं। प्रशासन तक पहुँच न हो पाने के कारण स्थानीय लोग नक्सलियों के अत्याचार का शिकार होते हैं। अशिक्षा और विकास कार्यों की उपेक्षा ने स्थानीय लोगों एवं नक्सलियों के बीच गठबंधन को मज़बूत बनाया है। नक्सलवादियों की सफलता की वज़ह उन्हें स्थानीय स्तर पर मिलने वाला समर्थन रहा है, जिसमें अब धीरे-धीरे कमी आ रही है। सरकार नक्सली चरमपंथ से निबटने के लिये बहुआयामी रणनीति अपना रही है। इसमें सुरक्षा एवं विकास से संबंधित उपाय तथा आदिवासी एवं अन्य कमज़ोर वर्ग के लोगों को उनका अधिकार दिलाने से संबंधित उपाय शामिल हैं। सरकार वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे, कौशल विकास, शिक्षा, ऊर्जा और डिजिटल संपर्कता का यथासंभव विस्तार करने के भी प्रयास कर रही है।

100 HP से ज्यादा पावर देने वाली 5 सबसे सस्ती गाड़ियां, कीमत सुनते ही बनेगा खरीदने का प्लान!

अपने इस लेख में हम आपके लिए ऐसी ही 5 कारों की लिस्ट लेकर आए हैं। ये गाड़ियां 100 एचपी से ज्यादा की शक्ति प्रदान करती हैं और इनकी कीमतें भी किफायती हैं। Mahindra XUV300 को 1.2-लीटर थ्री-पॉट टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है जो 108 एचपी जेनरेट करता है। आइए सभी कारों के बारे में जान लेते हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। मौजूदा समय में लोग बेहतरीन फीचर्स के साथ-साथ पॉवरफुल इंजन वाली किफायती कार खोजते हैं। अपने इस लेख में हम आपके लिए ऐसी ही 5 कारों की लिस्ट लेकर आए हैं। ये गाड़ियां 100 एचपी से ज्यादा की शक्ति प्रदान करती हैं और इनकी कीमतें भी किफायती हैं।

Mahindra XUV300

Mahindra XUV300 को 1.2-लीटर थ्री-पॉट टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है, जो 108 एचपी जेनरेट करता है। पेट्रोल से चलने वाली XUV300 की कीमत 7.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

Tata Nexon

Tata Nexon का 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 118 एचपी की अधिकतम शक्ति उत्पन्न करता है। इसकी कीमत 8.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

Maruti Suzuki Brezza

Maruti Suzuki Brezza को 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है, जो 102 एचपी की पावर पैदा करता है। वर्तमान में इस सब-4 मीटर एसयूवी की कीमत 8.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

Maruti Suzuki Ertiga

ब्रेज़ा की तरह मारुति सुजुकी अर्टिगा को भी कंपनी के 1.5-लीटर K15C माइल्ड-हाइब्रिड इंजन के साथ पेश किया गया है, जो 102 hp पावर पैदा करता है। इस एमपीवी की कीमत 8.64 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

Tata Altroz iTurbo

Tata Altroz iTurbo में 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है जो 108 hp की पावर देता है। अल्ट्रोज़ आईटर्बो संस्करण की कीमत 9.1 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

कार रेडिएटर का रखें खास ध्यान, इन टिप्स को जरूर करें फॉलो

कार चलाने वाले कार का काफी ध्यान रखते हैं। कार को बेहतर कंडीशन में रखने के लिए ये जरूरी भी होता है। कार के कई उपकरण बेहद नाजुक होते हैं, जिनका अधिक ख्याल रखना होता है, ऐसा न करने पर वह उपकरण खराब हो सकते हैं। कार का एक ऐसा ही उपकरण है, जिसका नाम है कार रेडिएटर। कार के इस उपकरण के बारे में अक्सर लोगों को कम जानकारी होती है। ऐसे में नीचे कुछ टिप्स दिए गए हैं, जिनका आपको ध्यान रखना है।

क्या होता है कार रेडिएटर

कार रेडिएटर गाड़ी को सही तरीके से चलाने में अहम भूमिका निभाता है। आसान भाषा में कहे तो ये कार के इंजन को ठंडा रखने का काम करता है। इसका मुख्य काम इंजन को कूलिंग देना होता है। जब भी कार में पेट्रोल डाला जाता है तो इससे एक ऊर्जा निकलती है, ये ऊर्जा इंजन को बहुत गर्म कर देती है, ऐसे में रेडिएटर इंजन को कूलिंग देने का महत्वपूर्ण कार्य करता है।

रेडिएटर लीकेज

कार रेडिएटर में अक्सर देखा गया है कि उसमें किसी तरह की लीकेज की परेशानी आ जाती है। कार के पुराने होने पर कई बार रेडिएटर में क्रेक, सील का टूटना और कोई कट हो सकता है। ऐसे में इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए रेडिएटर को बदल देना चाहिए।

जंग लगा हुआ कूलेंट

अक्सर ये भी देखा गया है कि समय के साथ कार रेडिएटर में जंग लग जाता है। हालांकि जंग इसकी क्षमता पर असर नहीं डालता है, मगर इसके कूलिंग सिस्टम पर बुरा प्रभाव जरूर डालता है। इतना ही नहीं, जंग लगने पर वाटर पंप के प्रदर्शन पर भी काफी खराब असर पड़ता है। इससे इंजन की क्षमता पर भी बेहद बुरा प्रभाव पड़ता है।

होसे की समस्या

कार के रेडिएटर में कई बार होसे की परेशानी आ जाती है। होसे दो तरह के होते हैं, ऊपर वाला होसे रेडिएटर के ऊपरी हिस्से से जुड़ा होता है। वहीं, नीचे वाला होसे रेडिएटर के नीचे वाले भाग से जुड़ा होता है। ये रबर और सिंथेटिक से बना होता है। ऐसे में कई बार इसमें क्रैक आ जाता है, इससे कूलिंग में लीकेज हो जाती है। इससे इंजन की सही से कूलिंग नहीं हो पाती है।

अगर आपने कार में कराए ये बदलाव, तो रद्द हो सकता है इंश्योरेंस

कार में बदलाव करवाना भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आपकी कार में मूल रूप से बड़े बदलाव करना न सिर्फ गैरकानूनी है। बल्कि ऐसा करना आपकी बीमा पॉलिसी को भी रद्द कर सकता है।

नई दिल्ली। कार में बदलाव करवाना भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। क्योंकि अब वाहन मालिक अपने वाहनों में अपनी पर्सनल फीलिंग जोड़ना चाहते हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आपकी कार में मूल रूप से बड़े बदलाव करना न सिर्फ गैरकानूनी है। बल्कि ऐसा करना आपकी बीमा पॉलिसी को भी रद्द कर सकता है। आम तौर पर, दो तरह के कार बीमा होते हैं - थर्ड-पार्टी और कॉम्प्रिहेंसिव बीमा पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव बीमा पॉलिसी आपके वाहन को हुए नुकसान को भी कवर करता है। यहां हम आपको बता रहे हैं कि वाहन में किस तरह के बदलाव (मॉडिफिकेशन) आपके बीमा कवरेज को खतरे में डाल सकते हैं।

एक्सटीरियर अपडेट

पेंट का नया कोट (जैसा कि आरसी पर जिक्र किया गया है) या स्टिकर (संयमित मात्रा में) जैसे मामूली बदलावों में आम तौर पर कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन फ्लेयर्ड फेंडर, कस्टम हुड और चौड़े टायर जैसे व्यापक बॉडी वर्क मॉडिफिकेशन बीमा कंपनी के लिए चिंता का विषय हो सकते हैं। क्योंकि ये बदलाव वाहन की संरचनात्मक अखंडता (स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटि) और हैंडलिंग से समझौता कर सकते हैं। जिससे बीमाकर्ताओं की नजर में जोखिम बढ़ जाता है।

इसके अलावा, आफ्टर-मार्केट लाइट्स (अलग रंग और तीव्रता की) जैसे बदलाव वाहन की विजिबिलीटी पर असर डाल सकते हैं। अगर वाहन में कराए जाने वाले इन बदलावों के लिए पहले से अप्रूवल नहीं लिया गया है, तो बीमा क्लेम को खारिज हो सकता है।

परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन

टर्बोचार्जर या नाइट्रस ऑक्साइड सिस्टम का इस्तेमाल करके इंजन के परफॉर्मेंस को बढ़ाने जैसे बदलाव बीमा कंपनियों के लिए खास तौर पर चिंता का विषय होते हैं। ये बदलाव वाहन के पावर और स्पीड को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है।

इसी तरह, कार की ऊंचाई को कम करने या बढ़ाने के लिए सस्पेंशन सिस्टम में किए गए बदलाव, कार को एक कस्टम रूप दे सकते हैं। लेकिन यह कार की हैंडलिंग और ग्राउंड क्लियरेंस पर बुरा असर डाल सकते हैं। ऐसे मामलों में भी, बीमा कवरेज संबंधी चिंताओं का खतरा होता है।

मॉडिफिकेशन के समय बीमाकर्ता को क्यों बताना चाहिए?

जब आप बीमा करा रहे होते हैं, तो वे आपकी कार का डिटेल्स नोट करेंगे और पॉलिसी लागत की गणना करेंगे। यदि आप अपनी कार में बदलाव करते हैं और उसका मूल्य बढ़ जाता है, तो आपको बीमा कंपनी को इन बदलावों के बारे में बताना होगा।

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया जबरदस्त स्पीड से बना रही टू-व्हीलर्स, 80 लाख यूनिट के पार पहुंचा आंकड़ा

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने हाल ही में एक नए माइलस्टोन अचीव करने की घोषणा की है। दिग्गज दोपहिया वाहन निर्माता ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से 80 लाख वाहन दोपहिया वाहन तैयार कर लिए हैं। जापानी निर्माता 2006 से भारत में काम कर रहा है और अपने स्कूटर और मोटरसाइकिलों की रेंज के लिए लोकप्रिय बना हुआ है।

Suzuki Avenis 125 बना 80 लाखवां टू-व्हीलर

उत्पादित होने वाला 80 लाखवां टू-व्हीलर Suzuki Avenis 125 है, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में ब्रांड के खेरकी धौला प्लांट से ओरेंज कलर में बनाया गया था। सुजुकी ने भारत में पहली बार दोपहिया वाहनों का निर्माण शुरू करने के 19 साल के भीतर प्रभावशाली उपलब्धि हासिल की।

परिचालन शुरू करने के 13 वर्षों के भीतर ब्रांड ने पहले चार मिलियन प्रोडक्शन माइलस्टोन हासिल किया, जबकि पिछले दशक में बिक्री में तेजी आई और छह साल से भी कम समय में अगली चार मिलियन यूनिट आ गईं। कंपनी ने खुलासा किया कि आखिरी दस लाख यूनिट सिर्फ एक साल में जोड़ी गई हैं।

कंपनी ने क्या कहा?

इस ऐतिहासिक आंकड़े को हासिल करने के बारे में बोलते हुए, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के प्रबंध निदेशक, केनिची उमेदा ने कहा-8 मिलियन-यूनिट माइलस्टोन तक पहुंचना एसएमआईपीएल की विनिर्माण क्षमता का एक प्रमाण है। मैं ब्रांड में उनके निरंतर समर्थन और विश्वास के लिए अपने ग्राहकों और व्यापार भागीदारों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और हम बिक्री के बाद की सेवा और बेहतर आतिथ्य सत्कार के लिए निरंतर प्रयासों के माध्यम से उन्हें और अधिक खुश करने के लिए समर्पित हैं।

कंपनी के प्रोडक्ट

सुजुकी इंडिया प्लांट घरेलू और निर्यात परिचालन के लिए दोपहिया वाहनों का उत्पादन करता है। कंपनी अपनी 125 सीसी स्कूटर रेंज के लिए सबसे लोकप्रिय बनी हुई है, जिसमें सुजुकी एक्सेस 125, बर्गमैन स्ट्रीट 125 और एवेनिस 125 शामिल हैं। यह Gixxer और Gixxer SF 155 सहित मोटरसाइकिलों की रिटेल सेल भी करती है। इसके अलावा Gixxer 250, Gixxer 250 SF, V-Strom SX 250, V-Strom 800DE, Katana और Hayabusa भी फ्लीट का हिस्सा हैं।

2024 बजाज पल्सर N250 खरीदने का बना रहे हैं प्लान? यहां जानिए 5 बड़ी बातें

बजाज ने अपडेटेड Pulsar N250 में नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जोड़ा है। यह वही यूनिट है जिसने पल्सर N150 और पल्सर N160 पर अपनी शुरुआत की थी। नया क्लस्टर गियर पोजीशन इंडिकेटर मोबाइल नोटिफिकेशन अलर्टरियल टाइम फ्यूल एपिशियंशी और डिस्टेंस टू एम्पटी जैसी जानकारियां साझा करता है। सभी सुविधाओं के साथ 2024 बजाज पल्सर N250 की कीमत में मामूली बढ़ोतरी हुई है। अब इसकी कीमत 1.51 लाख रुपये एक्स-शोरूम है।

नई दिल्ली। Baja Auto इंडियन मार्केट में अपनी पल्सर रेंज को अपडेट करने पर काम कर रही है। हाल ही में घरेलू निर्माता ने 2024 Bajaj Pulsar N250 को लॉन्च किया है, जिसका पहला संस्करण हमने नवंबर 2021 में देखा था। आइए, अपडेटेड पल्सर एन250 में हुए 5 बड़े बदलावों के बारे में जान लेते हैं।

कॉस्मेटिक बदलाव

बजाज ऑटो ने अपडेटेड एन 250 में दो नई कलर स्कीम जोड़ी हैं। इसमें ग्लॉसी रेसिंग रेड और पर्ल मेटैलिक व्हाइट है। बजाज पल्सर N250 के लिए भी ब्रुकलिन ब्लैक कलरवे की पेशकश कर रहा है। रंगों के अलावा, नए ग्राफिक्स भी हैं जो तीनों रंगों को मिलते हैं।

नए फीचर्स

बजाज ने अपडेटेड Pulsar N250 में नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जोड़ा है। यह वही यूनिट है, जिसने पल्सर N150 और पल्सर N160 पर अपनी शुरुआत की थी। नया क्लस्टर गियर पोजीशन इंडिकेटर, मोबाइल नोटिफिकेशन अलर्ट,रियल टाइम फ्यूल एपिशियंशी और डिस्टेंस टू एम्पटी जैसी जानकारियां साझा करता है। इसके अलावा नॉर्मल ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर और फ्यूल गेज होंगे।

पहले से ज्यादा सुरक्षित

Pulsar N250 पहले से ही डुअल-चैनल एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आई थी। हालांकि, अब बजाज ने तीन एबीएस मोड- रोड, रैन और ऑफ-रोड जोड़े हैं। इसके अलावा इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी मौजूद है, जो रियर व्हील के फिसलने का पता चलने पर पावर कट कर देता है।

हार्डवेयर चेंज

पल्सर एन250 में एकमात्र हार्डवेयर परिवर्तन सामने में यूएसडी फोर्क्स को शामिल करना है। इसकी वजह से मोटरसाइकिल बेहतरीन राइडिंग क्वालिटी प्रदान करती है।

अपडेटेड प्राइस

सभी सुविधाओं के साथ 2024 बजाज पल्सर N250 की कीमत में मामूली बढ़ोतरी हुई है। अब इसकी कीमत 1.51 लाख रुपये एक्स-शोरूम है।

टोयोटा फॉर्च्यूनर को मिला हाइब्रिड इंजन, ADAS के साथ बढ़ गया माइलेज भी; भारत में होगी लॉन्च?

पारिवहन विशेष न्यूज

Toyota Fortuner MHEV पॉपुलर एसयूवी का माइल्ड-हाइब्रिड संस्करण है जो अपनी माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक को हाइलक्स एमएचईवी के साथ साझा करता है। इसका पिछले साल के अंत में अनावरण किया गया था। दक्षिण अफ्रीकी-स्पेक फॉर्च्यूनर एमएचईवी भारत में बेची जाने वाली फॉर्च्यूनर लेजेंडर से काफी मिलती-जुलती है जो एक्सटीरियर पेंट विकल्पों की एक विस्तृत सीरीज पेश करती है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। देश-विदेश में ऑटोमेकर्स पारंपरिक दहन इंजन (ICE) और इलेक्ट्रिक पावर का मिश्रण पेश करते हुए Hybrid Vehicles बना रहे हैं। इस तकनीक ने अपने पर्यावरणीय लाभों और बेहतर फ्यूल एफिशियंशी के कारण महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। हाइब्रिड वाहन सेगमेंट में Toyota ने अपनी पॉपुलर एसयूवी Fortuner को MHEV टेक्नोलॉजी के साथ पेश किया है। हालांकि, ये अभी केवल दक्षिण अफ्रीकी मार्केट में ही उपलब्ध है।

Toyota Fortuner MHEV में क्या खास?

Toyota Fortuner MHEV पॉपुलर एसयूवी का माइल्ड-हाइब्रिड संस्करण है, जो अपनी माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक को हाइलक्स एमएचईवी के साथ साझा करता है। इसका पिछले साल के अंत में अनावरण किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में लॉन्च के बाद इस हाइब्रिड एसयूवी के आने वाले महीनों में अन्य बाजारों में भी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है।

इंजन और परफॉरमेंस

दक्षिण अफ्रीकी-स्पेक फॉर्च्यूनर एमएचईवी भारत में बेची जाने वाली फॉर्च्यूनर लेजेंडर से काफी मिलती-जुलती है, जो एक्सटीरियर पेंट विकल्पों की एक विस्तृत सीरीज पेश करती है। हुड के तहत, इस एसयूवी में 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ 2.8-लीटर डीजल इंजन है। हाइब्रिड सेटअप अतिरिक्त 16hp और 42Nm का टॉर्क देता है, जिससे कुल आउटपुट 201 hp और 500 Nm का टॉर्क बढ़ जाता है। टोयोटा का दावा है कि फॉर्च्यूनर एमएचईवी अपनी हाइब्रिड तकनीक के कारण मानक फॉर्च्यूनर 2.8 डीजल की तुलना में 5 प्रतिशत अधिक फ्यूल-एफिशिएंट है।

फीचर्स

माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के अलावा, फॉर्च्यूनर एमएचईवी में टोयोटा सेफ्टी सेंस एडास सूट, 360-डिग्री कैमरा और कुछ मामूली आंतरिक कॉस्मेटिक बदलाव भी शामिल हैं। एसयूवी मानक के रूप में 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आती है और 2WD और 4WD दोनों वेरिएंट में उपलब्ध है।

फॉर्च्यूनर एमएचईवी और हाइलक्स

एमएचईवी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेश किया जा रहा है, भारत नियमित फॉर्च्यूनर और हाइलक्स मॉडल पर कायम है। भारत में टोयोटा के लाइनअप में वर्तमान में पेट्रोल, पेट्रोल-हाइब्रिड, पेट्रोल-सीएनजी और डीजल-संचालित मॉडल शामिल हैं। भारत में टोयोटा की डीजल माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक का भविष्य में परिचय अनिश्चित बना हुआ है।

इसके अलावा, टोयोटा अगले साल भारत में अपना पहला मास-मार्केट ईवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह ईवी मारुति ईवीएक्स एसयूवी की सिब्लिंग होगी, जो टिकाऊ गतिशीलता के लिए ब्रांड के समर्पण को उजागर करेगा।

विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस की प्रासंगिकता

कुलदीप चंद अग्निहोत्री

पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी के बयानों को भी इसी गहरी नजर से देखना चाहिए। वह अमरीका के लोगों को बताते रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान समर्थक इस्लामी आतंकवादियों से इतना डर नहीं है जितना राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से'

कर्नाटक विधानसभा में पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके सुरेश ने कहा कि केंद्र सरकार दक्षिण भारत के राज्यों को कम पैसा मुहैया करवाती है। इससे हो सकता है कि हम दक्षिण के राज्य भविष्य में भारत से अलग होने की सोचें। वैसे तो पूछा जा सकता है कि सुरेश बाबू को दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधि किसने बनाया? तमिलनाडु में कांग्रेस कामराज के बाद से लुप्त प्रजाति में शामिल हो चुकी है। डीएमके चुनाव के मौसम में उसे कन्धे पर इस लहजे में उठा लेती है जैसे नई पीढ़ी के ज्ञान के लिए ऐतिहासिक चीजों का प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन सुरेश बाबू ने जब से यह रहस्योद्घाटन किया है तब से कम से कम प्रदेश में कांग्रेस के लोगों में यह भय बैठ गया है कि कहीं पार्टी विभाजन को लेकर किसी एजेंडा पर तो नहीं चल रही? पिछले दिनों कर्नाटक में कांग्रेस की एक विशाल जनसभा हो रही थी। उसमें कांग्रेस में सोनिया गान्धी परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े भी मंचासीन थे। कांग्रेस के एक विधायक लक्ष्मण संवादी भी मंच पर थे। वे भाषण दे रहे थे। उनके मन में इच्छा हो रही थी कि वे मंच पर से 'भारत माता की जय' का नारा लगाएं। लेकिन डर रहे थे कि कहीं इस नारे से पार्टी अध्यक्ष बुरा न मान जाएं। कुछ देर तक लक्ष्मण के मन में डर और श्रद्धा के बीच द्वन्द्व चलता रहा होगा। लेकिन अन्त में राष्ट्रीयता की जीत हुई। उन्होंने मंच पर से ही मल्लिकार्जुन खडग़े से पूछा कि यदि आप बुरा न मनाएं तो मैं 'भारत माता की जय' का एक नारा लगा लूं। आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जानते हैं कि अब पार्टी में 'भारत माता की जय' या 'जय श्री राम' का जयघोष करना खतरे से खाली नहीं है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि कांग्रेस का आम कार्यकर्ता तो देश को अखंड रखने के लिए या फिर अखंड भारत के लिए लालायित है, लेकिन उसका नेतृत्व अपने संकुचित राजनीतिक हितों के लिए भारत को तोडऩे की हद तक भी जा सकता है।

महात्मा गांधी से लेकर सोनिया परिवार तक की यह यात्रा सचमुच चौंकाती है। यह यात्रा रघुपति राघव राजा राम से शुरू हुई थी और राम मंदिर के निर्माण के विरोध तक ही नहीं, बल्कि राम के अस्तित्व को ही नकारने तक पहुंच गई है। यही कारण है कि पार्टी प्रधान की हाजिरी में कांग्रेस का विधायक 'भारत माता की जय' का नारा लगाते हुए भी डरता है कि कहीं पार्टी एक्शन न ले ले। दरअसल पिछले कुछ अरसे से भाजपा ने जनसंघ के समय से चले आ रहे अपने अखंड भारत के संकल्प को ज्यादा जोर से कहना शुरू कर दिया है। तब भी शायद कोई इसको ज्यादा तवज्जो न देता यदि भाजपा ने भारतीय संविधान में से अनुच्छेद 370 को न हटा दिया होता। इससे लोगों में यह विश्वास जगने लगा है कि पार्टी घोषणा पत्र/संकल्प पत्र में जो लिखती है, उसे पूरा करती है। चाहे उसमें कितना ही समय क्यों न लगे। इसके पहले चरण में तो पाकिस्तान के कब्जे से वे इलाके मुक्त करवाना है जो उसने 1947 में कश्मीर पर हमला करके भारत से छीन लिए थे। इसके संकेत प्रधानमंत्री मोदी अनेक बार दे भी चुके हैं। इससे पाकिस्तान का चिंतित होना स्वाभाविक ही है। लेकिन लगता है पाकिस्तान से ज्यादा चिंता इससे कांग्रेस के नेतृत्व को हो रही है। उस चिंता को व्यक्त करने का तरीका सामान्य नहीं है। उसका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी देश को विभाजित करना चाहती है। आरोप इस प्रकार का है कि आम भारतीय को यह हज्म नहीं होता।

सोनिया गांधी परिवार ने ऐसा आरोप मुस्लिम लीग या सीपीएम पर लगाया होता तो शायद भारत के लोग इस पर ज्यादा आश्चर्यचकित न होते। लेकिन यह परिवार ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इन दोनों के साथ केरल में परिवार का राजनीतिक समझौता है। इसलिए उसने यह आरोप भाजपा पर लगाना आसान मान लिया। लेकिन भाजपा आखिर विभाजन करवाना कैसे चाहती है? परिवार का कहना है कि भाजपा नार्थ-साऊथ डिवाइड के रास्ते पर चल रही है। लेकिन लोग आखिर इसके लिए प्रमाण की मांग करेंगे ही। वैसे यह जरूरी नहीं है कि राहुल गांधी जो भी कहते रहते हैं, उसके लिए कुछ प्रमाण भी उनके पास होते ही हों। वे स्वयं को इस प्रकार के सभी बंधनों से आजाद मानते हैं। सुरेश बाबू का तर्क यदि गहराई से देखा जाए तो कुछ बातें स्पष्ट हो रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि 1. उत्तर भारत, पश्चिमी भारत और कुछ सीमा तक पूर्वी भारत के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, इसलिए केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। 2. दक्षिणी प्रान्तों के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन दक्षिणी क्षेत्रों से नाराज है। 3. भारतीय जनता पार्टी अपनी यह नाराजगी इन दक्षिणी राज्यों से बदला लेकर निकालती है। बदला लेने का तरीका यही अपनाती है कि इन राज्यों को कम पैसा आवंटित किया जाता है। 4. कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री डीके सुरेश इसका एक ही हल बताते हैं कि फिर दक्षिण के राज्यों को देश से अलग होना पड़ेगा। सुरेश बाबू के तर्कों को निश्चय ही देखना पड़ेगा।

सुरेश बाबू कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं। कर्नाटक में मुख्य रूप से दो ही राजनीतिक दल हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। वहां एक बार भाजपा और दूसरी बार कांग्रेस सत्ता में आती है। इससे कोई भी अक्लमंद आदमी यह तो नहीं कहेगा कि कर्नाटक के लोग भाजपा को वोट नहीं देते। दूसरा उदाहरण तेलंगाना का ले सकते हैं। तेलांगना में मुख्य रूप से तीन राजनीतिक दल हैं। कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी। इन तीनों दलों को कुछ अंतर से सम्मानजनक वोट मिलते हैं। इसलिए तीनों राजनीतिक दलों की स्थिति राज्य में बराबर है। शेष दक्षिण के तीन राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की स्थिति लगभग बराबर ही है। इन दोनों की स्थिति नगण्य है। इसका अर्थ हुआ कि दक्षिण के राज्यों में भाजपा और कांग्रेस की स्थिति लगभग बराबर ही है। फिर सुरेश बाबू किस हैसियत से मानते हैं कि कांग्रेस को सभी दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधि के तौर पर बोलने का अधिकार है।

सुरेश बाबू एक बात शायद भूल रहे हैं कि पिछले दिनों जब राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस का एक प्रत्याशी जीता था, तो कर्नाटक विधानसभा के भीतर ही उसके समर्थकों ने खुशी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। तब कांग्रेस के ही कुछ बड़े लोगों ने उसकी निंदा करने की बजाय यह तर्क दिया था कि पाकिस्तान हमारा मित्र देश है, उसकी बात करना गलत कैसे हो गया? शायद उसी के कारण कांग्रेस के आम कार्यकर्ता के मन में कहीं न कहीं डर बैठ गया है कि भारत माता की जय से कांग्रेस नेतृत्व चिढ़ता है और पाकिस्तान जिंदाबाद से नाराज नहीं होता। अंबेडकर को शायद कांग्रेस से इसी बात का अंदेशा था। इसीलिए उन्होंने संविधान सभा में अपने अंतिम संबोधन में चेतावनी दी थी कि हमें इस प्रकार की वृत्तियों से सावधान रहना होगा। इसी के कारण हमारा देश पूर्वकाल में गुलाम होता रहा है। हम अपने निजी स्वार्थों के कारण आपस में ही लडऩे लगे रहते हैं और विदेशी दुश्मन इसका लाभ उठाते हैं। आज लगता है अंबेडकर को जिस बात का डर था, कांग्रेस नेतृत्व अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के कारण उसी रास्ते पर चल पड़ा है। पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी के बयानों को भी इसी गहरी नजर से देखना चाहिए। वह अमरीका के लोगों को बताते रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान समर्थक इस्लामी आतंकवादियों से इतना डर नहीं है जितना राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से। सौभाग्य है कि कांग्रेस का आम कार्यकर्ता और देश की जनता कांग्रेस नेतृत्व की भारत को विभाजित करने की इस थ्यूरी से सहमत नहीं है। यही कारण है कि वह कांग्रेस नेतृत्व की इस देश विरोधी रणनीति से सचेत होकर उसे नकार रही है।

संपादक की कलम से

खरीफ का सुखद मानसून

मानसून भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए अब भी मायने रखता है। सुखद खबर है कि इस बार मानसून की औसत बारिश सामान्य से अधिक हो सकती है। देश भर में बारिश की कुल मात्रा, 5 फीसदी की त्रुटि के साथ, लंबी अवधि के औसत का 106 फीसदी हो सकती है। बारिश की संभावना जून और सितंबर के बीच जताई जा रही है। यह अनुमान और आकलन भारतीय मौसम विभाग का है। चूंकि बीते साल सामान्य से कम बारिश हुई थी, लिहाजा इस बार यह संभावना सुखद लग रही है। यदि बारिश सामान्य से अधिक हुई, तो लहलहाती खरीफ की फसलों का मानसून साबित होगा। सवाल हो सकता है कि क्या अब भी कृषि, किसान और उनके जरिए देश की अर्थव्यवस्था मानसून की बारिश के भरोसे है? देश का करीब 46 फीसदी कार्यबल कृषि क्षेत्र में काम करता है। यदि मानसून निरंतर रूप से बेहतर न रहे, तो ग्रामीण आमदनी और उपभोग की मात्रा कम हो सकती है। उनसे अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होगी। बहरहाल मौसम विभाग मई माह के अंत में बारिश के सुनिश्चित अनुमान की घोषणा कर सकेगा। फिलहाल समुद्री तापमान के ढर्रे में अपेक्षित बदलाव और उत्तरी गोलार्द्ध में बर्फ की मात्रा को देखते हुए सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान है। अभी भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में मध्यम 'अल नीनो' की स्थिति बनी हुई है। देश में सामान्य से अधिक मानसून की 31 फीसदी संभावना है, जबकि सामान्य से कम मानसून की 8 फीसदी संभावना है और कमजोर मानसून की संभावना मात्र 2 फीसदी जताई गई है। भारत में सिंचाई का विस्तार इतना हो चुका है कि देश की खेती सालाना बारिश के भरोसे ही नहीं है। 2002 और 2009 में कृषि का उत्पादन घटा था, क्योंकि बारिश कम हुई थी, लेकिन खाद्य सुरक्षा का कोई भी संकट सामने नहीं आया, लिहाजा उन दोनों अनुभवों को भूल जाना चाहिए।

बेशक सामान्य मानसून कम भी रहा है, तो भी कृषि उत्पादन का रुझान बढ़ोतरी की तरफ रहा है। भारत में 60 फीसदी से अधिक सिंचाई नलकूपों (ट्यूबवेल) के जरिए होती है। यदि भूजल की कमी को लगातार रिचार्ज करके पूरा किया जाता रहे, तो 75 फीसदी सालाना रिचार्ज दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान ही हो जाता है। हम 59 फीसदी से अधिक भूजल को सालाना तौर पर बाहर निकालते हैं, लेकिन कई राज्यों में भूजल की कमी का ऐसा संकट है, जो देश को चिंतित करता रहा है। पंजाब और हरियाणा का उदाहरण सामने है। भारत की समग्र खाद्य सुरक्षा के लिए पंजाब और हरियाणा बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन राज्यों में कई जगह भूजल स्थिरता के बिंदु से भी नीचे है। भूजल को स्थिर और टिकाऊ बनाए रखना जरूरी है। अर्थात भूजल उतना होना चाहिए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु भारत की 'साइबर सिटी' है। वहां तमाम बड़ी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर मौजूद हैं। ऐसे शहर में पेयजल का संकट है, तो यह शर्मनाक स्थिति है। निरंतर पेयजल की उपलब्धता और पनबिजली उत्पादन के लिए जलाशयों का स्तर दुरुस्त होना चाहिए। पंजाब और हरियाणा में कुल भूजल निकालने का औसत, देश भर की तुलना में, 2022 में क्रमशः 164.15 फीसदी और करीब 136 फीसदी था। उप्र में भूजल निकालने का यह औसत करीब 71 फीसदी है। कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण पश्चिमी उप्र में भूजल का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, जो चिंतित संकेत है। भूजल के स्तर को स्थिर और निरंतर बनाए रखने के लिए बारिश का पानी जमा करते रहना भी जरूरी है।

यदि मौसम विभाग का अनुमान सही साबित हुआ, तो यह भूजल को रिचार्ज करने का भी सकारात्मक प्रयास किया जा सकता है। दुर्भाग्य है कि बारिश के पानी को जमा करने और फिर उसे भूजल के तौर पर इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति हमारे देश में 100 फीसदी नहीं है। भारतीय कृषि की नियति जलवायु-परिवर्तन पर भी आश्रित होगी, इसके आसार दुनिया भर में बनते जा रहे हैं, लिहाजा मानसून की बारिश का सम्मान करना सीखें।

राय

नसीब में चुनावी खुमार

हिमाचल में टिकट आबंटन की सर्कस में कई पिंजरे, कई दीवारें, कई मजमून और कई जमूरे करतब दिखा रहे हैं। आश्चर्य यह कि चार लोकसभा सीटों के हिसाब में भी हम राजनीति के खंभों पर टंगे हैं। जनता के नसीब में चुनावी खुमार का यह आलम कि यह सदी भी बंटी हुई गुजर रही है। सामाजिक विभाजन में राजनीति की चोंच इतनी लंबी हो गई है कि अपनी ही टेढ़ी कलों में उससे सीधा खड़ा नहीं हुआ जाता और फिर नेताओं का आयात इस शर्त पर कि किसी फैसले की हर घड़ी में हम उसी दौर में घिर रहे हैं, जो अतीत के पन्नों को बर्बाद करते रहे। आश्चर्य यह कि चुनाव के ऊंट उन्हीं प्राथमिकताओं में नेताओं को ढो रहे, जो न प्रदेश के काम आए और न समय में पहचाने गए। जिक्र अब यह कि कहां पंडित से पंडित लड़ाऊं या पंडित से राजपूत को भिड़ाऊं। फलां नेता के वर्चस्व में उसकी औलाद को आजमाऊं। हर रोज हिमाचल की सियासत जातिवाद, क्षेत्रवाद, अवसरवाद और परिवारवाद के पिंजरे में जाकर सोच रही है और जनता को भी भ्रम है कि इस तरह दीवारें टूटेंगी। हमारे नेता वे नहीं जो हम सोच रहे हैं, बल्कि वो हैं जो समाज को टुकड़ों में विभक्त कर सकते हैं। इसलिए टिकट आबंटन में जातियों के मंच ऊंचे और विचारधारा कहीं धरातल पर दब रही है। आश्चर्य यह कि विचारधारा की चिडिया कम से कम हिमाचल में विलुप्त होती जा रही है। रोते हैं वे हार जो कभी तेरी गर्दन पे चढ़े थे, आज उन्हीं को झुका कर तूने विपक्ष को चूम लिया। हिमाचल की राजनीति में जिस तेजी से राजनीतिक प्राणी फडफ़ड़ा रहे हैं, उसे देखकर विचारधारा गौण हो जाती है। गगरेट की जनता जिस दृश्य में चुनाव देख रही है वहां पूर्व विधायक राकेश कालिया का कांग्रेस में आना, शोला है या शबनम, कौन जानता है। कब भाजपा में चले जाएं या लौट के कांग्रेस में आ जाएं, यह एक चुनाव भर का अंतर है। हर तरफ चुनाव की गोपियां नाच रही हैं, भंवरे गीत गा रहे हैं और कहीं मधुमक्खियों के छत्ते में शहद रखा है। कसौटी यही हैं कि भरे बाजार में उतर जाएं तो कुछ तो दाम या दान मिलेगा। पार्टियों के टिकट के अभयदान में छह कांग्रेसी विधायक भाजपा के हो गए। छिक्के टूट रहे हैं और यह उस जनता के सामने हो रहा है जो स्वयं को सियासत की जागरूकता में पारंगत समझती है। जनता के पास कुछ टुकड़े, कुछ विवाद, कुछ जातिगत प्रयोग, कुछ गारंटियां, कुछ मुफ्तखोरी और कुछ स्वार्थी सपने। हम सीमा रेखा में रहकर बदलाव ढूंढ रहे हैं या अपने तूफानों से लडऩे के लिए चिराग खोज रहे हैं। आश्चर्य यह कि हिमाचल अपनी बोलियों में भाषा का सेतु नहीं जोड़ पाया और इसीलिए भाषावाद के सहारे समाज बोरियों में बंद है। हद तो यह कि यही एकमात्र राज्य है जहां 'धामवाद' भी चल रहा है। मेरी धाम उससे बेहतर के नारे पर मदरे झगड़ रहे हैं और पता नहीं उड़द की दाल उबलकर कितनी सूख गई है। प्रदेश के लिए सोचने की तासीर इतनी संकीर्ण रहेगी, तो फिर मंत्री बनकर भी नेता विधायक ही रहेंगे। ऐसे में क्या हमारे सांसद सत्रह विधानसभा क्षेत्रों के साथ न्याय कर पाएंगे। सत्रह विधानसभा क्षेत्रों में ही सही संस्कृति के सेतु पुष्ट करने होंगे। बोलियों से भाषा और खान-पान में धाम का चरित्र राज्य स्तरीय करना ही पड़ेगा। विडंबना यह है कि हिमाचल के गौरव की बात सैन्य बलिदानों में तो होती, लेकिन हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक उद्गार अभी भी क्षेत्रवाद में फंसे और यही क्षेत्रवाद अस्थिर सरकारों का मुखिया बनने की हिमाकत कर रहा है, जहां काम के बजाय राजनीतिक संतुलन में ही सरकारें समय और शक्ति बर्बाद कर रही हैं।

डा. देवेंद्र गुप्ता

सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ती कांग्रेस

हिमाचल के राजनीतिक परिदृश्य और कांग्रेस के नेताओं के बयानों को देख कर अब यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस अब हिंदुत्व के मुद्दे पर नरमी दिखाती अग्रसर हो रही है'

कांग्रेस को सबसे बड़ी और पुरानी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल था। सबसे बड़ी होने का रुतबा अब भारतीय जनता पार्टी ने कब का कांग्रेस से छीन लिया है। उसको अब पुरानी पार्टी ही बन कर संतोष करना पड़ रहा है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर बड़ी गहनता के साथ देश पर शासन करते हुए राजनीतिक दुर्घटना को अंजाम दिया। बहुसंख्यक हिंदुओं को सहिष्णुता का तो हमेशा पाठ पढ़ाया गया, परंतु अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति को अधिमान दिया गया। हिंदू मतदाताओं ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, फिर भारतीय जनसंघ, जनता पार्टी और अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी में शरण ली और इस तरह भाजपा का अभ्युदय हिंदू धर्म की अस्मिता को लेकर और अल्पसंख्यक तुष्टिकरण व आतंकवाद के विरोध में हुआ। अटल-आडवानी की युति ने भारतीय जनता पार्टी के रथ को हांकते हुए कई राज्यों में और केंद्र में सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की। कांग्रेस भी इसी बीच इन राजनीतिक झंझावातों को झेलते हुए भाजपा के बढ़ते कदमों को रोकने में सफल होती नजर आई और सरदार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में दो बार केंद्र में सरकार बनाने में सफल हुई। 2014 के चुनावों में बड़े स्तर पर हुए घपले, भ्रष्टाचार तथा राम मंदिर निर्माण का मुद्दा इतना हावी रहा कि कांग्रेस को केंद्र में और राज्यों में जबरदस्त हार का मुंह देखना पड़ा और भाजपा केंद्र में सत्ता हथिया पाने में सफल रही।

अब जबकि 2024 के लोकसभा चुनावों की बिसात बिछ चुकी है तो कांग्रेस के कर्णधारों को भाजपा की राजनीति से यह बात साफ समझ में आ गई है कि भारत जैसे हिंदू बहुल वोटरों के देश में अब उनकी जनभावनाओं को नहीं दबाया जा सकता है। इसीलिए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हिंदू हितैषी दिखने/दिखाने के लिए देश के मंदिरों की शरण में जाने लगे हैं और अपने को जनेऊधारी बताने लगे हैं। यहां तक कि राहुल की दोनों पद्यात्राओं में मंदिरों में आस्था, मठाधीशों और शंकराचार्यों से आशीर्वाद प्राप्त करना प्रमुखता के साथ एजेंडा में रहे। हिमाचल में भी कांग्रेस का शीर्ष राजनीतिक वीरभद्र परिवार अपने को सनातनी और 'हिंदू होने पर गर्व है' कहलाने में नहीं हिचकिचाया है। छह बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के बेटे और कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य ने 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का बाकायदा ऐलान कर दिया था। केन्द्रीय नेतृत्व की लाइन के विपरीत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने भी आस्था जताई। सरकार के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों ने भी यही दोहराया कि वो भी हिंदू हैं, पर वो राम मंदिर दर्शनों को बाद में जाएंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिमाचल की राजनीति के शिखर पुरुष वीरभद्र सिंह एक अच्छे प्रशासक ही नहीं बल्कि सुलझे हुए चुनावी रणनीतिकार भी थे। पिछली सदी के आठवें दशक में देश-प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की आहट और उपस्थिति दर्ज होने लगी थी। उस समय हिमाचल के मुख्यमंत्री के तौर पर वीरभद्र सिंह प्रदेश की राजनीति में काबिज हो गए थे। वीरभद्र का शासन समय और भाजपा का आरोहण काल एक ही है।

वो धर्म को व्यक्ति की आस्था का विषय मानते थे। धर्म में उनकी गहरी आस्था थी। मंदिरों के जीर्णोद्धार का कार्य, विशेषकर धर्म पीठों और काष्ठ कुणी शैली के मंदिरों के रखरखाव में विशेष ध्यान देते थे। उनके राज में मंदिरों को सरकारी अधिनियम के तहत अधिगृहित करते हुए प्राप्त आय को जनकल्याण में लगाया गया। प्रदेश में 2007 को धर्मांतरण पर अधिनियम लाया गया और बूढ़े, गरीब, असहाय माता-पिता को भरण पोषण का कानून पारित हुआ। ये कल्याणकारी कदम ऐसे थे जिन्होंने प्रदेश के हिंदू बहुल वोटरों को कांग्रेस से जोड़े रखा था। परंतु वीरभद्र आरएसएस की हिंदुत्व वाली विचारधारा को सांप्रदायिकता फैलाने वाली व नफरत पैदा करने वाली मानते थे। समाज में ऐसे विघटनकारी संस्थान को एक समय में बैन भी किया था। इसके बावजूद वीरभद्र ने चार-पांच दशक पहले अपने प्रदेश में समझ लिया था कि बहुसंख्यकों की अनदेखी भारत जैसे देश के लिए और राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के लिए अहितकारी होगी। हिमाचल में हिंदू बहुल आबादी होने के नाते हिंदू वोटरों ने सदैव उनका साथ दिया। जब राम मंदिर के निर्माण की बात आई तो अयोध्या को वह प्रति वर्ष नियम के साथ दान भेजते रहे। यही कारण है कि राम मंदिर निर्माण सभा ने वीरभद्र परिवार को न्योता भेजा और उनके बेटे, कांग्रेस के युवा आइकॉन विक्रमादित्य ने अपने पिता का मान रखते हुए और स्वयं राम भगवान में आस्था जताते हुए अयोध्या का निमंत्रण स्वीकार किया। कांग्रेस जैसा इतना बड़ा राष्ट्रीय दल भाजपा से मुकाबिल होने के लिए अपने से छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ आज गठबंधन करने को मजबूर हुआ जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में हिंदू धर्म को मानने वाले कुल जनसंख्या का 95.17 फीसदी हैं, जिनमें मुसलमान कुल आबादी का 2.18 फीसदी हैं और ईसाई कुल आबादी का 0.18 फीसदी हैं।

प्रदेश के 12 में से 11 जिलों में हिंदू बहुसंख्यक आबादी है। स्पष्ट है कि मुसलमान और ईसाई आबादी की संख्या इतनी भी नहीं है कि वे चुनावों के परिणामों को प्रभावित कर सकें। इनमें भी 56 प्रतिशत उच्च जाति के हैं जिनमें राजपूत 28 और ब्राह्मण 20 फीसदी हैं। वैश्य-क्षत्रिय 8 फीसदी बैठते हैं। शेष निचली जाति के हिंदू आते हैं जिनको सभी पार्टियां लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हैं। हिमाचल के राजनीतिक परिदृश्य और कांग्रेस के नेताओं के बयानों को देख कर अब यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस अब हिंदुत्व के मुद्दे पर नरमी दिखाती अग्रसर हो रही है, पर इस ऐहतियात के साथ कि कहीं दूसरे वर्गों का वोटर उनसे छिटक न जाए। प्रदेश में हिंदू वोटर कांग्रेस के साथ जुड़े रहें, इसलिए भी अब यह रणनीति अपनाई जा रही है। इस मुद्दे पर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान काबिलेगौर है। वह कहते हैं कि 'भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। उनसे बड़े हिंदू हम हैं और यहां देव समाज के लोग रहते हैं। बेशक मध्य भारत में भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती आई है, मगर हिमाचल प्रदेश में हिंदुत्व कार्ड काम नहीं करेगा। हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है।'

पूरन सरमा

साहित्य से उनका संन्यास...

बहुत दिनों तक तो साहित्यकार ढोलकी राम जी तय नहीं कर पाए कि उन्हें साहित्य में डटे रहना चाहिए अथवा आउट हो जाता चाहिए। परंतु उन्हें बाद में 'केवल्य' प्राप्त हुआ कि कोई स्वनामधन्य आलोचक उन्हें साहित्य के मैदान में पटखनी देकर चारों खाने चित करे, इससे पूर्व ही स्वयं के तथा साहित्य के हित में इस क्षेत्र को त्याग देना चाहिए। इसलिए एक दिन उन्होंने साहित्य से संन्यास की घोषणा कर दी। ढोलकी राम जी द्वारा साहित्य से पलायन का समाचार जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गया। मुझ तक आया तो मैं सकते में आ गया। तय नहीं कर पाया कि इस घटना से साहित्य की क्षति हुई है या उनकी क्षति। सारी स्थितियों पर छाए संशय के बादल दूर करने की दृष्टि से एक दिन मैं उनके निवास पर जा पहुंचा। अत्यन्त चिंतामग्न मुद्रा में मैंने पूछा-'सुना है आपने साहित्य से पलायन कर लिया है?' 'पहले संशोधन कीजिए-यह पलायन नहीं संन्यास है। पलायन क्या पुरुष करते हैं। मैंने साहित्य में पनपते भीषण प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए उसकी रक्षार्थ संन्यास का कदम उठाया है।' ढोलकी राम जी बोले। मैंने कहा-'थोड़ा संन्यास का खुलासा कीजिए। गृहस्थ से संन्यास लेना तो समझ में आता है, परंतु साहित्य में संन्यास सर्वथा नई घटना है। क्रिकेट और फिल्मों में संन्यास भी सुना है, परंतु साहित्य में नया प्रयोग है यह।' 'साहित्य भी लाल क्रिकेट की तरह खेल है-जब तक चौके-छक्के लगते रहे, तो डटे रहो।

ज्यों ही बिगडऩे लगे, मैदान छोडऩा कृतित्व एवं व्यक्तित्व के लिए हितकारी होता है। फिल्मों के अभिनय की तरह यह नाटकबाजी भी है। साहित्यकार का चेहरा लगा कर जीना पड़ता है। जब लगे कि आप बेनकाब हो रहे हैं, तो स्थितियों पर से कुहासा हटे, इससे पहले ही साहित्य से पिंड छुड़ा लेना चाहिए।' 'लेकिन ऐसी नौबत क्या थी। यदि आप साहित्य में बने भी रहते तो इससे अनिष्ट क्या होने वाला था? यदि आपने संन्यास ले लिया है तो आप साहित्यकार से घट कर अथवा बढक़र क्या हो गए हैं?' मैंने पूछा। 'देखो भाई, साहित्य में बड़ा धान-मसान हुआ है। हर ऐरा-गैरा-नत्थू-खैरा साहित्यकार बन गया है। पत्रकार भी अपने आपको लेखक समझने लगा है। भला फिर साहित्य की गरिमा घटेगी अथवा बढ़ेगी? साहित्य का अवमूल्यन हो, इससे पहले मैंने यह कदम उठा लिया। इससे मेरे साहित्यकार का जो अनिष्ट होने वाला था वह बच गया। हुआ कुछ नहीं है, बस फर्क यही पड़ा है कि मेरा 'साहित्यकार' कायम है तथा मैं आदमी बन गया हूं।

पहले व्यर्थ में साहित्यकार को आदमी पर ओढ़े रहना पड़ता था।' ढोलकी राम जी ने समझाया। मैं बोला-'लेकिन सुनने में यह आया है कि आप चुकने लगे थे। नए लोगों के सामने आपका लिखा एकदम कूड़ा लगने लगा था। अखबार-पत्रिकाएं तथा प्रकाशक आपको छापने से कतराने लगे थे एवं आलोचकों ने आपके साहित्य को अत्यंत निम्न कोटि का ठहराया है। ये स्थितियां और विकृत तथा विकट हों, इससे पहले ही आपने साहित्यकार को बचाने के लिए संन्यास ले लिया।' 'इसमें नई बात क्या है? मैं स्वयं बता रहा हूं कि 'साहित्यकार' को बचाने के लिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। परंतु यह बात बिल्कुल बेबुनियाद है कि नए लेखकों के सामने मैं टिक नहीं पा रहा था-अतः मैं भाग खड़ा हुआ। असलियत तो यह है कि नए लेखक साहित्य का सत्यानाश करने पर तुले हैं।'

इनसाइड

चौथी तिमाही में विप्रो के प्रॉफिट और रेवेन्यू में गिरावट,

देश की चौथी सबसे बड़ी IT फर्म विप्रो ने शुक्रवार (19 अप्रैल) को वित्त वर्ष 2023-24 की आखिरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का जनवरी-मार्च तिमाही में नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 8 प्रतिशत घटकर 2835 करोड़ रुपये रहा। अगर वित्त वर्ष 2022-23 की आखिरी तिमाही की बात करें तो विप्रो को 3074 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था।

नई दिल्ली। देश की चौथी सबसे बड़ी IT फर्म विप्रो ने शुक्रवार (19 अप्रैल) को वित्त वर्ष 2023-24 की आखिरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का जनवरी-मार्च तिमाही में नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 8 प्रतिशत घटकर 2,835 करोड़ रुपये रहा।

अगर वित्त वर्ष 2022-23 की आखिरी तिमाही की बात करें, तो विप्रो को 3,074 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था। पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में विप्रो का नेट प्रॉफिट 2,700 करोड़ रुपये रहा था। इस लिहाज से देखें, तो तीसरी तिमाही के मुकाबले चौथी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 प्रतिशत बढ़ा है।

विप्रो का चौथी तिमाही में ऑपरेशन से भी 4.2 प्रतिशत घटा है। पिछले की समान तिमाही में यह 23,190 करोड़ रुपये था, जो इस बार 22,208 करोड़ करोड़ रहा।

पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा तो महंगाई में होगी वृद्धि, वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता की स्थिति

परिवहन विशेष न्यूज

बैंक ऑफ क्रेडिट द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। वैल्यूएशन ने चेतावनी दी है कि यदि पश्चिम एशिया में संघर्ष का दबाव बना तो इसका दूरगामी परिणाम होगा और वैश्विक कमोडिटी की सीमा में बढ़ोतरी होगी और दबाव का दबाव बढ़ेगा।

नई दिल्ली। बैंक ऑफ क्रेडिट द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। बढ़ते संघर्ष ने लोगों को सुरक्षित निवेश के लिए प्रेरित किया है और यही वजह है कि सोना, डॉलर और येन की सीमा में बढ़ोतरी दिख रही है।

वैश्विक कमोडिटी की सीमा में होगी बढ़ोतरी!

वैल्यूएशन ने चेतावनी दी है कि यदि पश्चिम एशिया में संघर्ष का दबाव बना, तो इसका दूरगामी परिणाम होगा और वैश्विक कमोडिटी की सीमा में बढ़ोतरी होगी और दबाव का दबाव बढ़ेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस तरह के इवेंट एग्रीमेंट से लेकर नौकरी तक के लिए चल रहे प्रयास को धीमा कर दिया जाएगा और रिजर्व बैंक द्वारा रेट में कटौती की संभावना अब भविष्य में और आगे बढ़ा दी गई है।

तनाव ने वैश्विक बाजारों को सदमे में डाल दिया है, जिससे अनिश्चितता और अस्थिरता की लहर शुरू हो गई है। एशियाई बाजार खुद को खतरे में पा रहे हैं, मुद्राएं नीचे कारोबार कर रही हैं और तेल की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। भारत के सेंसेक्स में पिछले 4 सत्रों में गिरावट देखी गई, जिसका असर खासतौर पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और बैंकिंग शेयरों पर पड़ा है।

सोना, डॉलर और येन की बढ़ी वैल्यू

भारत की 10-वर्षीय उपज शुरू में स्थिर रही, लेकिन अब 7.21 प्रतिशत पर उच्चतर कारोबार कर रही है, जो मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और उनके संभावित आर्थिक प्रभावों पर चिंताओं को दर्शाती है। बढ़ते संघर्ष ने सुरक्षित-संपत्तियों की ओर पलायन को प्रेरित किया है। इसमें सोना, डॉलर और येन सभी महत्वपूर्ण लाभ का अनुभव कर रहे हैं।

विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि मध्य पूर्व में व्यापक संघर्ष के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिससे संभावित रूप से वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि होगी और मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ेगा। इस तरह के घटनाक्रम मुद्रास्फीति से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पैदा करते हैं, फेडरल रिजर्व दर में कटौती की संभावना अब भविष्य में और आगे बढ़ गई है।

USA का क्या हाल?

भू-राजनीतिक तनाव की इस पृष्ठभूमि के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रम बाजार की स्थिति कठिन बनी हुई है, बेरोजगार दावे 212,000 पर स्थिर हैं, जो अनुमानित 215,000 से थोड़ा कम है। हालांकि, अमेरिका में मौजूदा आवास बिक्री में 4.3 प्रतिशत की गिरावट आई है, जिससे आर्थिक दृष्टिकोण में और जटिलता आ गई है।

जापान का ये पूर्वानुमान

बैंक ऑफ जापान के गवर्नर ने मुख्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में मामूली कमी के बावजूद फरवरी में 2.8 प्रतिशत से मार्च में 2.6 प्रतिशत तक कम होने के बावजूद, येन के मूल्यह्रास के मुद्रास्फीति प्रभाव का मुकाबला करने के लिए और अधिक दरों में बढ़ोतरी की संभावना का संकेत दिया है।

मौजूदा अनिश्चितता के बावजूद, वैश्विक शेयर उच्च स्तर पर बंद हुए, क्योंकि निवेशकों ने मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव, फेड अधिकारियों की तीखी टिप्पणियों और अमेरिका के बेरोजगार दावों सहित प्रमुख विकासों पर नजर रखी।

ऑल टाइम हाई पर सोने-चांदी की कीमतें

सोने और चांदी की कीमतें ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। HDFC Securities के मुताबिक दिल्ली में सोने की कीमत में 400 रुपये की बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। इसके साथ सोना 74100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी भी 100 रुपये की बढ़त के साथ 86600 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है।

नई दिल्ली। सोने और चांदी की कीमतें आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई हैं। ग्लोबल ट्रेंड के चलते सोने के दाम आज 74 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार कर गई है। HDFC Securities के मुताबिक, दिल्ली में सोने की कीमत में 400 रुपये की बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। इसके साथ सोना 74,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले गुरुवार को सोने की कीमत 73,700 रुपये थी।

सोने की तरह चांदी की कीमत में 100 रुपये की बढ़त देखने को मिली है। इस तेजी के साथ चांदी भी 86,600 रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। HDFC Securities के सीनियर एनालिस्ट सौमिल गांधी ने बताया कि सोने और चांदी की कीमत में यह तेजी विदेशी मार्केट से मिले संकेतों के चलते देखने को मिली है।

सोने की कीमत में तेजी ग्लोबल मार्केट में मांग के चलते देखने को मिली है। इसके साथ ही इजरायल और ईरान युद्ध की आशंका के चलते भी सोने की कीमत में तेजी देखने को मिल रही है।

मार्केट एनालेटिक्स के अनुसार, अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों सहित रिपोर्टों की सीरीज में इस साल सोने की मांग में तेजी देखने को मिलेगी। कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व के शीर्ष अधिकारियों का मनना था कि वे कुछ समय से लिए ब्याज दरें ऊंची रखी जा सकती हैं।

सिप्ला पर लगा करोड़ों रुपये का जुर्माना, गलत दावे के कारण हुई कार्रवाई; जानिए

सिप्ला पर माल और सेवा कर प्राधिकरण ने 1.83 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सिप्ला ने बताया कि तथ्यों के आकलन और प्रचलित कानून के आधार पर वह इस संबंध में अपीलीय प्राधिकारी के पास आवश्यक अपील दायर करेगी। शुक्रवार को खत्म हुए कारोबारी सत्र में सिप्ला के शेयर मामूली गिरावट के साथ 1347 .00 रुपये की कीमत पर बंद हुए।

नईदिल्ली। देश की दिग्गज फार्मा कंपनी Cipla पर GST अथॉरिटी ने 1.83 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। अथॉरिटी का कहना था कि कंपनी ने एजुकेशन सेस पर गलत दावे किए थे। कंपनी को सीजीएसटी और सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट से नोटिस मिला है, जिसमें उसे केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 और महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम के तहत 1,83,17,388 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश मिला है। यह जानकारी सिप्ला ने नियामक फाइलिंग के दौरान दी है।

इसमें आगे बताया गया है कि यह आदेश जीएसटी प्राधिकरण द्वारा इस तर्क पर दिया गया है कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2017-18 में एक्साइज से जीएसटी में स्विच के दौरान कंपनी ने एजुकेशन सेस पर अमान्य क्रेडिट दावा किया गया था। इस पर कंपनी पर जुर्माना और वसूली का आदेश दिया गया है।

नोटिस के खिलाफ अपील करेगी कंपनी

सिप्ला ने आगे कहा कि तथ्यों के आकलन और प्रचलित कानून के आधार पर वह इस संबंध में अपीलीय प्राधिकारी के पास आवश्यक अपील दायर करेगी। इसमें कहा गया है कि उक्त आदेश के कारण कंपनी की वित्तीय स्थिति या संचालन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सिप्ला के शेयरों का हाल

शुक्रवार को खत्म हुए कारोबारी सत्र में सिप्ला के शेयर मामूली गिरावट के साथ 1347.00 रुपये की कीमत पर बंद हुए। कंपनी ने पिछले छह महीने में 12 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

IMF ने अब इस बात को लेकर की भारत की तारीफ, कहा - चुनावी साल में भी आपने...

आईएमएफ में एशिया व प्रशांत विभाग के निदेशक कृष्णा श्रीनिवासन ने बताया ''इस समय भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 6.8 प्रतिशत की वृद्धि बहुत अच्छी है। महंगाई कम हो रही है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि मुद्रास्फीति को तय लक्ष्य तक लाया जाए।'' उन्होंने कहा कि राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना खासकर चुनावी वर्ष में मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण बात है।

नई दिल्ली। IMF applauds India भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति को लेकर वैसे तो दुनियाभर की रेटिंग एजेंसियां तारीफ करती रहती हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) भी पहले भारत की तारीफ कर चुका है।

अब एक बार फिर आईएमएफ (IMF) ने भारत की प्रशंसा की है। चुनावी साल में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने को लेकर इस बार आईएमएफ भारत का मुरीद हो गया है। साथ ही आईएमएफ ने यह भी कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है और अब भी दुनिया का ब्राइट स्पॉट बनी हुई है।

आईएमएफ में एशिया व प्रशांत विभाग के निदेशक कृष्णा श्रीनिवासन ने बताया, ''इस समय भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 6.8 प्रतिशत की वृद्धि बहुत अच्छी है। महंगाई कम हो रही है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि मुद्रास्फीति को तय लक्ष्य तक लाया जाए।'' उन्होंने कहा कि "राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना खासकर चुनावी वर्ष में, मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि देश चुनावी वर्ष में राजकोषीय साहसिक कार्य शुरू करते हैं।"

'सरकार ने अनुशासन बनाए रखा'

श्रीनिवासन ने कहा, ''इस सरकार ने अनुशासन बनाए रखा है। मुझे लगता है यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आखिरकार ठोस 'मैक्रो फंडामेंटल' ही वह आधार है जिसके आधार पर देश समृद्ध होते हैं और टिकाऊ वृद्धि कायम रखते हैं। इसलिए इसे बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है।''

'कई झटकों को झेलकर आगे बढ़ा भारत'

उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले वर्षों में कई झटकों को झेला और उनसे सफलतापूर्वक पार पाया है। यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा, ₹इस वर्ष, 2024-25 के लिए 6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगा रहे हैं जिसमें निजी उपभोग और सार्वजनिक निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। महंगाई धीरे-धीरे कम हो रही है और अब यह 5 प्रतिशत से नीचे है।"

श्रीनिवासन ने कहा, "यदि आप मैक्रो फंडामेंटल को देखें, तो वे काफी ठोस हैं, चुनावी वर्ष होने के बावजूद, सरकार ने राजकोषीय अनुशासन का पालन किया है। आप रिजर्व स्थिति को देखें, यह मजबूत है। यदि आप समग्र मैक्रो फंडामेंटल को देखें, तो यह काफी अच्छा है।" उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के जोखिम मोटे तौर पर संतुलित हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बताया था कि 5 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.98 बिलियन डॉलर बढ़कर 648.562 बिलियन डॉलर के नए शिखर पर पहुंच गया। इसके पिछले हफ्ते भी विदेशी मुद्रा भंडार 2.951 बिलियन डॉलर बढ़कर 645.583 बिलियन डॉलर हो गया था, जो अब तक का उच्चतम स्तर था।

कुछ दिनों पहले अरबपति बना था नारायण मूर्ति का पांच महीने का पोता, अब मिला इतने करोड़ का डिविडेंड

इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने पिछले महीने अपने पोते एकाग्र रोहन मूर्ति को अरबपति बनाया था। उन्होंने एकग्रह को इन्फोसिस के 15 लाख शेयर दिए थे जिसकी वैल्यू 240 करोड़ रुपये थी। अब इन्फोसिस ने अपने चौथी तिमाही के नतीजों के बाद 28 रुपये के डिविडेंड का भी एलान किया है। आइए जानते हैं कि इससे एकग्रह को कितने रुपये मिलेंगे।

नई दिल्ली। दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने पिछले महीने अपने पोते एकाग्र रोहन मूर्ति को अरबपति बनाया था। उन्होंने एकाग्र को इन्फोसिस के 15 लाख शेयर दिए थे, जिसकी वैल्यू 240 करोड़ रुपये थी।

अब इन्फोसिस ने अपने चौथी तिमाही के नतीजों के बाद 28 रुपये के डिविडेंड का भी एलान किया है। इसमें 20 रुपये का फाइनल और 8 रुपये का स्पेशल डिविडेंड शामिल है। इससे एकाग्र रोहन मूर्ति की सिर्फ डिविडेंड से 4.2 करोड़ रुपये की कमाई हो गई है।

इन्फोसिस ने बताया कि फाइनल डिविडेंड और स्पेशल डिविडेंड को 31 मई को फिक्स किया जाएगा। इसका भुगतान 1 जुलाई को होगा।

इन्फोसिस में एकाग्र के कितने शेयर हैं?

नारायण मूर्ति के पोते एकाग्र के पास

इन्फोसिस के 15 लाख शेयर हैं, यानी कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 0.04 प्रतिशत है। अगर इन्फोसिस के शेयरों की मौजूदा मार्केट प्राइस के हिसाब से जोड़े, तो यह करीब 210 करोड़ रुपये होता है। इस हिसाब से एकाग्र को 4.2 करोड़ रुपये का डिविडेंड मिलेगा।

एकाग्र नारायण मूर्ति के बेटे रोहन मूर्ति और बहू अपर्णा कृष्णन के बेटे हैं। वह पिछले साल 10 नवंबर को बेंगलुरु में पैदा हुए थे। एकाग्र के पिता रोहन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की है और वह सॉफ्टवेयर फर्म सोरोको (Soroco) चलाते हैं। वहीं, अपर्णा कृष्णन की बात करें, तो वह मूर्ति मीडिया को संभालती हैं।

ब्रिटेन के पीएम के ससुर हैं नारायण मूर्ति

इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति के दो और ग्रैंडचिल्ड्रेन हैं। दरअसल, ब्रिटेन के नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति की शादी ऋषि सुनक से हुई है, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। सुनक और अक्षता के दो बच्चे हैं, कृष्णा और अनुष्का।

दिसंबर तिमाही के आखिर में अक्षता मूर्ति के पास इन्फोसिस में 1.05 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। वहीं, सुधा मूर्ति की 0.93 और रोहन मूर्ति की 1.64 प्रतिशत थी।

Air India की तेल अवीव के लिए उड़ानें रद्द, इजरायल-ईरान विवाद को देखकर 30 अप्रैल तक फ्लाइटें कैंसिल

एयर इंडिया ने तेल अवीव के लिए अपनी सारी उड़ानों को 30 अप्रैल 2024 तक के लिए रद्द कर दिया है। इस अवधि के दौरान जिन यात्रियो की टिकट बुकिंग है उन्हें अपनी टिकट को कैंसिल कराने और किसी दूसरी तिथि को टिकट बुक करने की सुविधा दी जा रही है।

नईदिल्ली। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात को देख कर एयर इंडिया ने तेल अवीव के लिए अपनी सारी उड़ानों को 30 अप्रैल, 2024 तक के लिए रद्द कर दिया है। कंपनी ने बताया है कि वह हालात पर लगातार नजर बनाये हुए है और उक्त अवधि के दौरान जिन यात्रितों के आरक्षित टिकट हैं उनके संपर्क किया जा रहा है व आवश्यक सूचना उपलब्ध कराई जा रही है।

इस अवधि के दौरान जिन यात्रियो की टिकट बुकिंग है उन्हें अपनी टिकट को कैंसिल कराने और किसी दूसरी तिथि को टिकट बुक करने की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इजरायल ने शुक्रवार को सुबह ईरान के कुछ शहरों पर हमला किया है। ईरान का कहना है कि इससे कोई बड़ी हानि नहीं हुई है।

1500 उड़ानें रद्द

ईरान ने अपने तीन शहरों तेहरान, शिराज और इस्फाहान के एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। इस युद्ध के बाद भारत आने वाली दर्जनों उड़ानों को अब रास्ता बदलना पड़ रहा है क्योंकि वह ईरान व इजरायल के हवाई मार्ग का इस्तेमाल नहीं कर रही।

इस मार्ग से दुबई जाने वाली

तकरीबन 1500 उड़ानों के भी रद्द होने की सूचना है। फ्लाई दुबई, टर्किश एयर, एमिरैट्स समेत कई एयरलाइनों ने कहा है कि वह स्थिति का जायजा ले रही हैं और इसके बाद ही आगे का फैसला करेंगी।

दुबई की फ्लाइट भी कैंसिल

Air India ने दुबई में बाढ़ के चलते फ्लाइट ऑपरेशन में आ रही परेशानी के चलते फ्लाइट कैंसिल करने का एलान किया है। एयरलाइंस ने शुक्रवार को कहा कि परिचालन फिर से शुरू होते ही वह प्रभावित ग्राहकों को उड़ानों में जगह देने की कोशिश कर रही है। इसमें कहा गया है कि जिन ग्राहकों ने 21 अप्रैल तक यात्रा के लिए टिकटों के साथ फ्लाइट बुक की हैं, उन्हें दूसरी तिथि पर बुक करने या कैंसिल पर पूरा रिफंड दिया जाएगा।

16 साल के निचले स्तर पर आया गेहूं का स्टाक, अधिकारी ने बताया किस वजह से आई कमी

सरकार को इस साल किसानों से तीन करोड़ से 3 .2 करोड़ टन गेहूं खरीद के अपने लक्ष्य को हरहाल में हासिल करना होगा ताकि अगले सीजन में स्टॉक का स्तर बफर मानक से ऊपर रहे। सरकार ने 2022 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। माना जा रहा है कि आम चुनाव के बाद सरकार शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने पर विचार कर सकती है।

नई दिल्ली। सरकारी गोदामों में रखे गए गेहूं का स्टॉक 16 सालों के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के आंकड़ों पर गौर करें तो अप्रैल की शुरुआत में गेहूं का भंडार कुल 7.5 मिलियन टन (75 लाख टन) था, जो एक साल पहले के 8.35 मिलियन टन (83.5 लाख टन) से कम था। एक अधिकारी ने बताया कि गेहूं के स्टॉक में कमी आई है, क्योंकि मूल्य को स्थिर रखने के लिए एक करोड़ टन गेहूं खुले बाजार में बेचना पड़ा। पिछले एक दशक में, 1 अप्रैल को गेहूं का स्टॉक औसतन 16.7 मिलियन टन था।

उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है कि गेहूं का स्टॉक एक करोड़ टन से नीचे नहीं जाए। मुंबई स्थित एक डीलर ने कहा कि सरकार को इस साल किसानों से तीन करोड़ से 3.2 करोड़ टन गेहूं खरीद के अपने लक्ष्य को हरहाल में हासिल करना होगा ताकि अगले सीजन में स्टॉक का स्तर बफर मानक से ऊपर रहे। सरकार ने 2022 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। माना जा रहा है कि आम चुनाव के बाद सरकार शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने पर विचार कर सकती है।

भारत 2022 और 2023 में अपने गेहूं खरीद लक्ष्य को हासिल करने में विफल रहा था, क्योंकि ज्यादा गर्मी की वजह से फसल का आकार छोटा हो रह गया था। वहीं रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर कमी होने के कारण मांग बढ़ी थी, इसके बावजूद भारत ने 2022 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था।

डीलर ने कहा, "अगर सरकार आवश्यक मात्रा खरीदने में विफल रहती है... तो वह आम चुनाव के बाद शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देने पर विचार कर सकती है।"

अमृतसर निर्वाचन क्षेत्र 019 अमृतसर दक्षिणी बूथों की जांच की गई

अमृतसर (साहिल बेरी) डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी श्री घनशाम थोरी के आदेशानुसार आज अमृतसर दक्षिणी निर्वाचन क्षेत्र 019, नगर निगम, अमृतसर के सहायक रिटर्निंग अधिकारी-सह-अतिरिक्त आयुक्त श्री सुरिंदर सिंह ने विधानसभा क्षेत्र के बूथों की जांच की, चेकिंग के दौरान अपर आयुक्त द्वारा बूथों एवं एएमएफ (एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज) का विशेष रूप से निरीक्षण किया गया.

उन्होंने मौके पर मौजूद सेक्टर सुपरवाइजरों को निर्देश दिया कि अगर किसी भी तरह के बूथों पर कोई छोटी-मोटी कमी है तो उसे अगले 48 घंटे में दुरुस्त कर रिपोर्ट दें. अपर आयुक्त ने कहा कि उपायुक्त के आदेशानुसार बूथों पर आने वाले मतदाताओं एवं पोलिंग पार्टियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. इस अवसर पर सेक्टर पर्यवेक्षक श्री बलजिंदर सिंह एवं चुनाव प्रभारी श्री संजीव कालिया उपस्थित थे।

21 राज्यों की 102 सीटों पर पहला फेज संपन्न

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। 2024 के लोकसभा महाकुंभ वोटिंग का पहला चरण छिट-पुट घटना के बाद शांतिपूर्ण संपूर्ण हो गया। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर पहले चरण के मतदान में 5 बजे तक मध्यप्रदेश में 65 %, राजस्थान में 50 %, बंगाल में सबसे ज्यादा 77 % वोटिंग करने की सूचना है। बता दें कि सीटों के हिसाब से यह सबसे बडा फेज है। इसमे 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। मतदान शाम 6:00बजे तक चला। इस महा-मत पर्व में दिव्यांगजनों ने भी बड-चढ कर अपने मतों का प्रयोग किया। इसके लिए भले वह अपने परिचितों की गोदी, बैसाखी के सहारे मतदान केन्द्र तक पहुंचे।कुल वोटिंग प्रतिशत 60 फीसदी तक दर्ज किया गया। वोट टर्न आउट ऐप के मुताबिक शाम 5:00बजे तक सबसे ज्यादा मतदान बंगाल में 77.57 % फीसदी हुआ। सबसे कम वोटिंग बिहार में 46.32 % हुई है।वही 21 राज्यों में वोटिंग का एवरेज 62.8 & है। वोटिंग के दौरान मणिपुर के विष्णु पुर में फायरिंग, बंगाल के कूचविहार में हिंसा और छत्तीसगढ के बीजापुर में ग्रेनेड ब्लास्ट की खबर है। ब्लास्ट में एक असिस्टेंट कमांडेंट और जवान घायल है। मणिपुर की दो लोकसभा सीटों (मणिपुर इनर और मणिपुर आउटर सीट के कुछ हिस्सों में 26 अप्रैल को भी वोटिंग होगी। उल्लेखनीय है पहले चरण में 1625 उम्मीदवार चुनाव लड रहे हैं। इनमें 1491 पुरूष ,134 महिला कैंडीडेट है। इस पहले फेज के चुनावी दंगल में 8 केंद्रीय मंत्री,एक पूर्व राज्यपाल भी इस बार चुनाव मैदान में है। इस फेज के बाद 26 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग होगी। कुल.7 चरण में 543 सीटों पर 1 जून। मतदानखत्म होगा।सभी सीटों के परिणाम 4 जून को आएगें। पहले चरण के मतदान में 18 लाख से अधिक कर्मचारियों को तैनात किया गया। 16.63 करोड से अधिक वोटर्स ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। इनमें 8.4 करोड पुरूष,8.23 करोड महिलाए और 11,371 थर्ड जेंडर शामिल है। इस चरण में 20-29 साल के युवा वर्ग की संख्या 3.51 करोड है,जिन्होने अपने मत का प्रयोग किया। इसके अलावा 35.67 लाख नए मतदाताओ को जोडा गया। जिन्होने पहली बार अपना मतदान किया।

कमल रंगोली बना भाजपा के पक्ष में वोट का दिया संदेश

आधी आबादी का भाजपा के पक्ष में जिले में जोरदार संपर्क अभियान

परिवहन विशेष न्यूज

भीलवाड़ा। भाजपा महिला मोर्चा का भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के बनेड़ा-शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के पक्ष में जोरदार संपर्क अभियान चलाया गया, साथ ही सहाडा विधानसभा में महिलाओं ने कमल रंगोली बना भाजपा के पक्ष में वोट देने का संदेश दिया

भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मंजू पालीवाल के नेतृत्व में शाहपुरा विधानसभा बनेड़ा मंडल में संयोजक स्नेहलता गगरानी के सानिध्य में घर-घर जाकर संपर्क किया प्रचार प्रसार किया की पंपलेट पत्रक वितरण किये, लोक सभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल को भारी मतों से विजय बनाने के लिए कहां 26 अप्रैल को अधिक से अधिक वोट देने और दिलाने को कहा है इस कार्यक्रम में जिला महामंत्री सुमित्रा पोरवाल,चंदा सोनी, बबीता अग्रवाल, लाड सोनी, रेखा सोनी, सरिता सोनी ,ज्योति सोनी, डिंपल की नियति रितु नियति गिरजेश शर्मा आदि महिलाएं उपस्थित थी।

20 अप्रैल को गृहमंत्री अमित शाह के शक्करगढ़ सभा में आने के लिए निमंत्रण दिया। सहाड़ा विधानसभा में कमल के फूल की रंगोली बनाकर संयोजक मीरा किराड़ एवं सहसंयोजक विमला चेचनी के द्वारा कोट गांव में महिलाओं से संपर्क किया और मोदी की योजनाओं से अवगत कराया और लाभार्थी बहनों से बातचीत की प्रचार प्रसार किया, इस कार्यक्रम में सुमित्रा पोरवाल बबीता अग्रवाल गीता देवी त्रिवेदी रायपुर मंडल अध्यक्ष प्यारी बाई शर्मा प्यारी बाई शर्मा धापू बाई शर्मा प्रेम बाई तिवारी सीता देवी शर्मा शांता देवी शर्मा मांगी देवी वैष्णव चंदा देवी शर्मा लीला देवी वैष्णो वर्षा शर्मा पारस बाई चेचानी, ज्ञान बाई ईनाणी ,कजू बाई शर्मा, प्रेम देवी वैष्णव ,भावना लोहार, दिव्या लोहार आदि महिलाएं उपस्थित थी ।

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की सभा शनिवार को शक्करगढ़ में सभा में अधिक से अधिक संख्या में पधारने का अग्रवाल ने किया आग्रह

अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा भाजपा लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल दूसरे दिन भी आसीन्द विधानसभा के दौरे पर रहे। जहां उन्होंने कई सभाओं को सम्बोधित करते हुये शनिवार को केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की होने वाली सभा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचाने का आमजन से आग्रह किया।

लोकसभा मीडिया प्रभारी विनोद झुर्रानी ने बताया कि भाजपा लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल ने आसीन्द विधानसभा की सभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि देश की भविष्य भाजपा के हाथों में सुरक्षित है। भाजपा की सरकार ने देश की आन्तरिक एवं बाहरी सुरक्षा इतनी मजबूत कर दी है कि अच्छे से अच्छा देश भी भारत पर आंख उठाने से पहले सोचने को मजबूर हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह की बहुआयामी सोच ने भारत देश को एक मजबूत एवं विकसित देश के रूप में विश्व में अपनी पहचान बना दी है।

लोकसभा प्रत्याशी ने आसीन्द विधानसभा की मोड़ का निम्बाहेड़ा, करजालिया, ब्राह्मणों की सरेरी, नारायणपुरा, पालड़ी, कांवलास, बराणा, दड़ावत, परासोली, आकड़सादा, मोटरास, संग्रामगढ़, चतरपुरा, ओज्याड़ा, मोठी, मोगर, बदनौर, परा में सभाओं का आयोजन कर आमजन से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की व सघन जन सम्पर्क किया।

जन सम्पर्क के दौरान विधायक जब्बर सिंह, पूर्व विधायक रामलाल गुर्जर, तेजवीर सिंह दौलतगढ़, चौयरमेन देवीलाल साहू, संयोजक अशोक तलाइच, फोजमल गुर्जर, पवन मुंगड़, राजेन्द्र रावत, अभिजीत सिंह, पूर्व उपजिला प्रमुख रामचन्द्र सेन, घनश्याम सिकलीघर, गोविन्द सिंह, फतेह सिंह चारण, शिव व्यास, जिला मंत्री भगवतीलाल, शांतिलाल गुर्जर, शिवराज अरोड़ा, भागचंद गुर्जर कांवलास, पचायत समिति सदस्य अमित सैन, अनिता उपाध्याय, गोपाल तेली, ईश्वर खटीक, धनराज माली, राजेन्द्र सिंह राठौड़, सिकन्दर अली, किरण सिंह, मेवाराम गुर्जर, मागुराम गुर्जर, नाथूराम गुर्जर, भैरू सिंह भाटी सहित सैकड़ो की संख्या में कार्यकर्ता एवं उद्योगपति उपस्थित थे।

अमृतसर की फूलकारी महिलाएं गुरदासपुर के ग्रीन कॉरिडोर कार्यक्रम का समर्थन करती हैं

परिवहन विशेष न्यूज

अमृतसर, (साहिल बेरी) अमृतसर की फूलकारी महिलाएं, एक समर्पित दानशील संगठन, गुरदासपुर में स्वास्थ्य प्राधिकरणों के साथ मिलकर खुशहाली के हर क्षण के लिए ग्रीन कॉरिडोर कार्यक्रम की शुरुआत का समर्थन करते हुए गर्व से उन्होंने आज ग्रीन कॉरिडोर कार्यक्रम के शुभारंभ का समर्थन किया।माननीय सिविल सर्जन गुरदासपुर, डॉ। हरभजन मंडी, और महानगरीय परिवार योजना अधिकारी गुरदासपुर, डॉ। तजिंदर कौर, के आदर्श मार्गदर्शन में, संगठन के प्रमुख, डॉ। रश्मि विज, एसएमओ, सीएचसी नौशेरा मजहा सिंह, के साथ, ग्रीन कॉरिडोर कार्यक्रम को उच्च जोखिम गर्भावस्था रोगियों के लिए बेहतर देखभाल और फॉलो-अप सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।कार्यक्रम के दौरान, हमारे महान सदस्य, डॉ। अमृता राणा, नेहा शर्मा, राधिका अरोड़ा, और डॉ। गुनीत कौर, एसएमओ, मूल्यवान जानकारी और समर्थन प्रदान करते हुए। डॉ। राणा, एक अनुभवी वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट, सर्वांगीण स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हुए सीरविकल कैंसर, इसके लक्षण, और रोकथाम के उपायों पर प्रकाश डालते हुए, उन्हें विशेष शक्ति प्रदान की।हम डॉ। राश्मि विज, एसएमओ, और इस पहल में शामिल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हृदय से धन्यवाद देते हैं। मिलकर, हम उच्च जोखिम गर्भावस्था रोगियों की सहज यात्रा, मातृत्व मृत्यु दरों को कम करने, और हमारे समुदायों में कुल संवृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित खड़े हैं।

लंबे समय तक झूठे मुकदमे का सामना कर रहे रिंका को वर्षों बाद मिला न्याय

आरोपित के अधिवक्ता अरविन्द पुष्कर के गंभीर तर्कों को सुनने के पश्चात न्यायालय ने किया बारी, अधिवक्ता अरविन्द पुष्कर द्वारा मजबूती एवं गंभीरता से न्यायालय में रखा गया अभियुक्त का पक्ष, अभियोजन अपना केस साबित करने में रहा असफल

परिवहन विशेष न्यूज

आगरा। जिला एवं सत्र न्यायालय दीवानी कचहरी में कल माननीय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) न्यायालय संख्या - 29 आगरा ने आरोपित रिंका उर्फ़ रिंकू को अधिवक्ता अरविन्द पुष्कर के गंभीर तर्कों को सुनने के पश्चात अपने एक आदेश में आरोपित को आरोप मुक्त कर दिया। वहीं, अभियोजन अपना केस साबित करने में असफल रहा। न्यायालय में आरोपित के विद्वान अधिवक्ता अरविन्द पुष्कर द्वारा मजबूती एवं गंभीरता से अभियुक्त का पक्ष रखा और लंबे समय तक झूठे मुकदमे का सामना कर रहे आरोपित को वर्षों बाद न्याय मिला।

इस सन्दर्भ में आरोपित के अधिवक्ता अरविन्द कुमार पुष्कर ने न्यायालय के आदेशानुसार बताया कि माननीय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) न्यायालय संख्या - 29 आगरा ने अपने एक आदेश में राज्य बनाम रिंका उर्फ रिंकू पुत्र सुरेश निवासी सेफऊ जिला धौलपुर मुकदमा संख्या 505/2018 अंतर्गत धारा - 363, 376, 377 भा.द.स. एवं धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 थाना खेरागढ़ जनपद आगरा के अंतर्गत आरोपित रिंका को अपराध में दोष मुक्त कर दिया। इस केस में रिंका उर्फ़ रिंकू के विरुद्ध आरोप लगाए जो माननीय न्यायालय में युक्ति युक्त संधेय से परे सिद्ध नहीं हुऐ और आरोपों को अभियोजन साबित करने में असफल रहा। इस आधार पर समस्त आरोपों को खारिज करते हुए माननीय न्यायालय ने मुकदमे में आरोपित को दोष मुक्त कर दिया।

दिल्लीवाले निकले सबसे बड़े भुलक्कड़, सफर में करते हैं सबसे बड़ी गलती; वीकेंड पर हो जाता है खेल!

एक प्रमुख कैब एग्रीगेटर सर्विस प्रदाता ने इस संबंध में खोई पाई वस्तुओं का सूचकांक जारी किया है। इसके तहत खोई पाई गई वस्तुओं से लेकर सर्वाधिक तौर पर भूलने वाले वस्तुओं का विवरण भी बताया है। कैब में जो वस्तुएं लोग सर्वाधिक रूप से भूलते हैं उसमें फोन लैपटॉप कपड़े चाबी हेडफोनपर्स पानी की बोतल गहने और घड़ी शामिल है।

नई दिल्ली। दौड़ती भागती हुई जिदंगी में दिल्ली वाले कैब में सर्वाधिक सामान भूल रहे हैं, जबकि कैब में सामान भूलने में दूसरा शहर मुबंई है। बेंगलुरु तीसरे स्थान पर है।

एक प्रमुख कैब एग्रीगेटर सर्विस प्रदाता ने इस संबंध में खोई पाई वस्तुओं का सूचकांक जारी किया है। इसके तहत खोई पाई गई वस्तुओं से लेकर सर्वाधिक तौर पर भूलने वाले वस्तुओं का विवरण भी बताया है।

शाम को होती है ज्यादा घटनाएं

कंपनी के केंद्रीय संचालन प्रमुख नीतिश भूषण के अनुसार कैब में जो वस्तुएं लोग सर्वाधिक रूप से भूलते हैं उसमें फोन, लैपटॉप, कपड़े, चाबी, हेडफोन,पर्स, पानी की बोतल, गहने और घड़ी शामिल है। ज्यादा भूलने की शिकायतें शुक्रवार से रविवार के बीच आती हैं। शाम को छह से आठ बजे के बीच यह घटनाएं ज्यादा होती हैं। जो अनोखी वस्तुएं कैब में लोग भूल रहे हैं, उसमें वाधयंत्र, सिक्के, गेट वाल्व, कानफ्रैल्कस और प्रसाद शामिल है।

नागरिक कैब सेवा प्रदाता कंपनी को ऐप के माध्यम से खोई हुई वस्तुओं पाने की जानकारी दे सकते हैं। जिसे कंपनी द्वारा ग्राहकों को लौटाया जाता है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे।
RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023